● वर्ष-5
● अंक-165
रायपुर, मंगलवार
24 फरवरी 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› संत गाडगे बाबा ने दिया ...

प्रदेश की जीएसडीपी में 11.57 फीसदी वृद्धि का अनुमान

वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, 6.31 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का दावा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक तस्वीर पेश की गई। वर्ष 2025-26 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.57 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। साय सरकार ने जीएसडीपी को 6.31 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना जताई है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 6.31 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे राज्य की विकास योजनाओं, अधोसंरचना विस्तार और निवेश बढ़ोतरी का परिणाम बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 10.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है।

कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर में तेज रफ्तार,आर्थिक सर्वेक्षण में तीनों प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान जताया गया

- कृषि क्षेत्र- 2025-26 में 12.53%वृद्धि का अनुमान
- उद्योग क्षेत्र- 10.26%वृद्धि का अनुमान
- सेवा क्षेत्र-13.15% वृद्धि का अनुमान

- स्थिर भावों पर कुल वृद्धि दर- 8.11%

2024-25 के आंकड़े

कृषि में 11.76%, उद्योग में 9.91%, सेवा क्षेत्र में 10.08% वृद्धि दर्ज की गई थी

निवेश का दिखेगा असर

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, धान खरीदी, कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार और सेवा क्षेत्र में बढ़ते निवेश का सकारात्मक असर प्रदेश में देखने को मिला।

प्रति व्यक्ति आय में भी उछाल

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपए होने का अनुमान है। यह वर्ष 2024-25 की तुलना में 10.07 प्रतिशत अधिक है। सरकार का दावा है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और रोजगार सृजन के प्रयासों से आम नागरिक की आय में वृद्धि हुई है।

आर्थिक सर्वेक्षण को आगामी बजट का आधार माना जा रहा है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़े यह संकेत देते हैं कि सरकार विकास और राजकोषीय संतुलन दोनों पर फोकस कर रही है। अब 24 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर राजनीतिक दलों और आम जनता की नजरें टिकी हैं, जहां इन अनुमानों को धरातल पर उतारने की रणनीति सामने आएगी।

मजबूत और संतुलित अर्थव्यवस्था का प्रमाण : साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को राज्य की मजबूत और संतुलित अर्थव्यवस्था का प्रमाण बताया है। समृद्ध किसान, मजबूत उद्योग और विस्तृत सेवा क्षेत्र को विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव करार दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए एक के बाद एक छह पोस्ट में कहा कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश का जीएसडीपी प्रचलित भावों पर बढ़कर 6,31,291 रूपए करोड़ अनुमानित है, जिसकी वृद्धि दर 11.57% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 12.53%, उद्योग में 10.26% और सेवा क्षेत्र में 13.15% वृद्धि का अनुमान यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ आज किसानों की समृद्धि और औद्योगिक मजबूती के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

हमारे लिए गर्व का विषय है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 12.53% वृद्धि अनुमानित है।

कृषि क्षेत्र में मजबूत विकास दर दर्ज हुई है, जो किसानों की मेहनत और हमारी

किसान-हितैषी नीतियों का परिणाम है। समृद्ध किसान ही विकसित छत्तीसगढ़ की नींव है। छत्तीसगढ़ आज देश की औद्योगिक ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उद्योग क्षेत्र में 10.26% वृद्धि अनुमानित है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान लगभग 49%है — जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। निवेश, रोजगार और अधोसंरचना विकास के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। सेवा क्षेत्र छत्तीसगढ़ की नई अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र में 13.15% वृद्धि अनुमानित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और डिजिटल सेवाओं में विस्तार से नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 दर्शाता है कि प्रदेशवासियों की आय लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर लगभग 1.79 लाख अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10.07 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। यह हमारी विकासोन्मुख नीतियों और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का परिणाम है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा

- **हमारा लक्ष्य है** - प्रदेश के हर परिवार की आय बढ़े, जीवन स्तर बेहतर हो और समृद्धि हर घर तक पहुंचे।
- **हमारा संकल्प है** -छत्तीसगढ़ के हर परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाना।
- **हमारी सोच है** - प्रदेश का विकास तभी सार्थक है, जब हर परिवार समृद्ध हो।
- **हमारा उद्देश्य स्पष्ट है** - विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर परिवार खुशहाल बने।

प्रमुख समाचार

पीएम मोदी दूसरी बार 25 को इजराइल दौरे पर जाएंगे

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से इजराइल दौरे पर जा रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में वह दूसरी बार इजराइल जाएंगे। वह 2017 में इजराइल गए थे। एक तरफ भारत के संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं तो वहीं इजराइल के साथ भी उसके लंबे समय से संबंध हैं। ऐसी

स्थिति में पीएम मोदी का फिर से इजराइल दौरा अहम माना जा रहा है। इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू 2025 में ही तीन बार भारत आने के प्लान बना चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रणनीतिक और विदेश मामलों के जानकार का कहना है कि पीएम मोदी के इजराइल दौरे से इससे भारत को फायदा होगा और उसे रणनीतिक बढ़त मिलेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसे समय में इजराइल का दौरा करने वाले हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में पीएम मोदी की इजराइल यात्रा भले ही थोड़ी अलग चीज लगे, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व है।

जन आशीर्वाद यात्रा का अमित शाह करेंगे अगुवाई

नईदिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेगी। यह यात्रा 28 फरवरी से शुरू होकर असम के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर नागरिकों के साथ

पार्टी का जुड़ाव मजबूत करना और केंद्र सरकार एवं असम राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और कल्याणकारी पहलों को उजागर करना है। भाजपा के एक वरिष्ठ सूत्र के अनुसार कि यात्रा के विभिन्न चरणों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। इनमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के साथ-साथ केंद्र और राज्य इकाई के अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा के दौरान जनसभाएं, रोड शो और सामुदायिक संवाद आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक विकास और शासन सुधारों में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जा सके।

सुब्रमण्यम की याचिका खारिज पर्याप्त आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक रिट याचिका खारिज कर दी। याचिका में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई एक सदस्यीय समिति को चुनौती दी गई थी। यह कमेटी तिरुमाला लड्डुओं के लिए कथित तौर पर मिलावटी

घी की सप्लाई से जुड़े मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सही विभागीय एक्शन के लिए बनाई गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की जा रही प्रशासनिक जांच और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच अलग-अलग दायरे में काम करती हैं। इसकारण दोनों प्रक्रियाएं साथ-साथ चल सकती हैं। स्वामी की याचिका में कहा गया था कि एक सदस्यीय समिति की जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित एसआईटी की जांच में दखल दे रही है। यह मामला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं में इस्तेमाल हुए घी में मिलावट के आरोपों से जुड़ा है। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालत की चिंता सिर्फ इतनी है।

किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर

किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिला के छात्रू-पासरकूट में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में क्षेत्र में सक्रिय जेश ए मोहम्मद संगठन के साथ जुड़े तीन आतंकी मारे गए, जिसके साथ ही क्षेत्र में चलाए गए अभियान त्राशि-1 में अभी तक चार आतंकी मारे गए हैं। जानकारी केक मुताबिक छात्रू में चले लंबे अभियान में रविवार सुबह पासरकूट के वानी

पुरा के करीब एक ढोक में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो गई, जिसमें 2-पैरा, आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी का दल शामिल था। इसी बीच सुरक्षा बलों ने ढोक को उड़ा दिया और ढोक की तलाशी दौरान सुरक्षा बलों ने पहले जले हुए दो शव और दो एके-47 बंदूकें बरामद की और शाम को सेना ने मलबे के नीचे से एक और आतंकी का शव और बंदूक बरामद की, जिसके साथ ही मारे जाने वाले आतंकियों की संख्या तीन हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पर तलाशी अभियान जारी है।

ओडिशा में 77 बांग्लादेशी घुसपैठिए की पहचान

भुवनेश्वर। ओडिशा में 77 लोगों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में की गई है, जिनमें से 73 को वापस उनके देश भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछले साल 2 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद, राज्य के सभी जिलों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक इन निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं. इस जांच अभियान के तहत अब तक 2261 संदिग्धों के पहचान दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है. इनमें से 2184 लोगों की पहचान भारतीय नागरिकों के रूप में हुई है, जिन्हें छोड़ दिया गया है. शेष 77 लोगों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में हुई है. भुवनेश्वर से दो और लोगों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है. वर्तमान में, राज्य में घुसपैठियों की पहचान का काम नियमित रूप से जारी है। भुवनेश्वर में 26, कटक में 15, बरहमपुर में 6, गंजम में 1, कंधमाल में 4, कोरापुट में 1, केंद्रपाड़ा में 3 और जगतसिंहपुर में 21 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में की गई है. पहचाने गए 77 बांग्लादेशियों में से 73 को वापस उनके देश (डिपोर्ट) भेज दिया गया है।

गिरगिट से ज्यादा तेज गति से रंग बदलते हैं ट्रंप

सनत जैन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। पिछले एक वर्ष में जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए हैं उनके निर्णय के कारण जिस तरह की अनिश्चित अमेरिका के साथ-साथ सारी दुनिया के देशों में देखने को मिल रही है, उसके बाद लोग यह कहने लगे हैं, कि गिरगिट भी देर से रंग बदलता है लेकिन ट्रंप उससे जल्दी रंग बदल लेते हैं। हाल ही में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए थे उसे निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैधानिक माना है। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया फैसला लिया, जिसमें 10 फ़ीसदी टैरिफ को लगाने का फैसला किया था। अदालत के फैसले के कुछ ही घंटे के बाद उन्होंने शुक्रवार को 10 फ़ीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन शनिवार को उसे बढ़ाकर 15 फ़ीसदी कर दिया। 24 फरवरी से 24 जुलाई तक सभी देशों की अलग-अलग दरों के स्थान पर अगले 150 दिन अर्थात 15 जुलाई तक 15 फ़ीसदी टैरिफ़ वसूल किया जाएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ने जा रहा है। भारत के फार्मा ?र पेट्रो पर तीन फ़ीसदी टेरिफ़ लगेगा लेकिन बाकी सभी चीजों पर अब 15 फ़ीसदी टैरिफ अमेरिका में जो भी माल भेजा जाएगा उस पर लगेगा। भारत के संबंध में बात की जाए तो पहले उन्होंने 50 फ़ीसदी टैरिफ लगाया, 2 फरवरी को अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति जताते हुए टैरिफ को 18 फ़ीसदी किया था। उसके बाद 10 फीसदी टैरिफ लगाया गया। अब उसे बढ़ाकर 15 फ़ीसदी कर दिया गया है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह की अनिश्चितता अमेरिका को लेकर सारी दुनिया में देखने को मिल रही है उसमें भले अभी ट्रंप को कुछ फायदा हो रहा हो लेकिन जिस तरह से अमेरिका की साख को बट्टा लग रहा है उसके बाद सारी दुनिया में यह धारणा बनने लगी है अमेरिका को जिस दिशा में डोनाल्ड ट्रंप ले जाना चाहते हैं। उसके कारण अमेरिका कुछ ही महीना में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अमेरिका के ऊपर ही पड़ रहा है। अमेरिका में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। अमेरिका की ट्रेजरी

से विभिन्न देशों ने अपना सोना और बांड के रूप में जमा राशि को निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका की जो विश्व में साख पिछले कई दशकों में बनी हुई थी वह तार-तार हो गई है। कारोबारी और विभिन्न देशों की सरकारों को अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं रहा, जिसके कारण अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानकर उन्होंने वैकल्पिक तरीके से सारी दुनिया के देशों से जो 15 फ़ीसदी टैक्स एक जजिया-कर की तरह वसूल करने की कोशिश की है, वह अपने निर्णय के माध्यम से दबाव बनाकर दुनिया के विभिन्न देशों में अपने परिवार और पारिवारिक कंपनियों को जो लाभ पहुंचाना चाहते हैं उसकी यह रणनीति चर्चा का विषय बन गई है। कारोबारी और विभिन्न देशों की सरकारें अमेरिका से दूरी बनाने लगी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी आंतरिक चुनौतियों राजनीतिक आधार पर बनना शुरू हो गई हैं। सड़कों पर उनका विरोध शुरू हो गया है। विभिन्न राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संघीय व्यवस्था को खत्म करने और डिक्टेटर वाले निर्णय लेने से बगावत जैसी स्थिति देखने को मिलने लगी है। अमेरिका कभी पूरी दुनिया का नेतृत्व करता था लेकिन अब यह स्थिति बदलती हुई दिख रही है। रूस, चीन जैसे देश अमेरिका के समानांतर एक नई वैकल्पिक व्यापारिक व्यवस्था विकसित करने की बात कर रहे हैं। वैकल्पिक मुद्रा तैयार कर रहे हैं। जिसको दुनिया के अन्य देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। अभी तक अमेरिका को जो डॉलर के कारण कमाई हो रही थी अब वह कमाई भी खतरे में पडती हुई दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दबाजी में है। उनके कार्यकाल का एक वर्ष एक माह लगभग खत्म हो चुका है उनके लिए 2 वर्ष और 11 में शेष हैं। इस बीच में वह अपने परिवार और अपने लिए वह सब कुछ कर लेना चाहते हैं जो वह सोचते हैं। लेकिन यह संभव नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के निर्णयों के कारण अमेरिका के साथ-साथ सारी दुनिया के देशों में उनका विरोध बढ़ता चला जा रहा है। व्यापार और संबंध में विश्वास होना जरूरी होता था। वह विश्वास डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक होकर मनमाने फैसले ले रहे हैं उसके बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही उनके खिलाफ अमेरिका में विद्रोह शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जिद्दी हैं। यह उनका व्यक्तिगत दुर्गुण है, जिसका खामियाजा आगे चलकर अमेरिका को चुकाना पड़ेगा। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा।

190 एकड़ सरकारी जमीन पर 135 कब्जाधारियों कराया खाली

कोरबा। जिले में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हटाए। करीब 90 एकड़ सरकारी जमीन पर लोगों ने फार्म हाउस और पक्के मकान बना रखे थे। दर्री के केसी जैन मार्ग पर जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ की गई है। सोमवार सुबह संयुक्त टीम के पहुंचते ही मौके पर हड़कंप मच गया। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। करीब 90 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर घर और फार्म हाउस बनाए गए थे। कब्जा करने वाले ज्यादातर बड़े ठेकेदार और रईस लोग बताए जा रहे हैं। कटघोरा एसडीएम ने 135 लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए थे। नोटिस के बावजूद लोगों ने जमीन खाली नहीं की थी। प्रत्येक कब्जाधारी ने 60 से 70 डेसिमल जमीन पर कब्जा कर रखा था। इस कार्रवाई में 4 से 5 जेएसईबी मशीनें लगाई गईं। कुछ लोग अपना सामान निकालने में सफल रहे, जबकि कुछ का सामान बुलडोजर से हटा दिया गया। इन जगहों को अय्याशी का अड्डा बना लिया गया था, जहां लोगों का जमावड़ा रहता था। कब्जे वाली जगहों पर कई पक्के मकान और सीट-छज्जा के घर भी मिले।

इस कार्रवाई में जिला प्रशासन की ओर से कटघोरा एसडीएम तन्मय खन्ना मौजूद थे। पुलिस प्रशासन की ओर से विमल पाठक भी मौके पर उपस्थित रहे। नगर निगम का तोड़ू दस्ता प्रभारी टीम के साथ कार्रवाई में लगा हुआ है। अवैध कब्जे हटाने की यह बड़ी कार्रवाई अभी भी जारी है। अवैध कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया था। इनमें कई बड़े ठेकेदार और संपन्न लोग शामिल थे। उन्होंने इन जमीनों पर घर, फार्म हाउस और अय्याशी के अड्डे बना रखे थे। पक्के मकानों के साथ-साथ सीट और छज्जा वाले घर भी पाए गए। यह अतिक्रमण नोटिस के बावजूद खाली नहीं किया जा रहा था।

बस्तर में पहली बार, एनसीसी एयर कैडेट्स जैसा फ्लाइंग एक्सपोजर, छात्राओं ने विमान को करीब से देखा

जगदलपुर। बस्तर में पहली बार स्कूली बच्चों को एनसीसी एयर कैडेट्स जैसा फ्लाइंग एक्सपोजर मिला। नारायणपुर के सुदूर अंचल के विद्यार्थियों ने जगदलपुर के माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर विमानन की बारीकियां समझीं। साथ ही उनके सपनों को नए पंख लगे। बस्तर के मां दंतेश्वरी हवाई अड्डे में नारायणपुर के स्कूली छात्रों को पहली बार उड़ान अनुभव मिला। यह जिला प्रशासन की विशेष पहल पर आयोजित एक उच्च-स्तरीय शैक्षणिक भ्रमण था। इसे बस्तर के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज किया गया है। छात्रों ने विमान को करीब से देखा और उसकी बारीकियों को समझा। उन्हें पहली बार विमान को इतने पास से देखकर काफी खुशी हुई। छात्रों ने अधिकारियों से विमान उड़ाने की कड़ी मेहनत और यहां तक पहुंचने के तरीकों पर सवाल पूछे। नारायणपुर जिले के सुदूर अंचलों के विद्यार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर था।यह भ्रमण सामान्य स्कूली विद्यार्थियों को एनसीसी वायु कैडेट्स की तर्ज पर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विमानन की अत्याधुनिक तकनीक समझाना था। साथ ही रक्षा सेवाओं में कॅरिअर की संभावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना था। इस पहल से विद्यार्थियों को भविष्य के लिए प्रेरणा मिली। यह कार्यक्रम रक्षा सेवाओं में युवाओं की रुचि बढ़ाने में सहायक होगा।

भ्रमण के दौरान एक जिज्ञासु छात्रा ने भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर से सीधा सवाल किया। उसने पूछा कि वह लड़ाकू विमान चालक कैसे बन सकती है। छात्रा के इस प्रश्न ने वहां मौजूद सभी अधिकारियों को प्रभावित किया। विंग कमांडर विवेक कुमार साहू ने राष्ट्र सेवा के इस गौरवशाली पथ की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया। विंग कमांडर साहू ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि एक सफल लड़ाकू विमान चालक बनने के लिए शारीरिक दृढ़ता अनिवार्य है। इसके साथ ही शैक्षणिक अनुशासन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तकनीकी विषयों में गहरी रुचि होना भी आवश्यक है। यह सभी गुण राष्ट्र सेवा के इस पथ पर सफलता दिलाते हैं।

धमतरी में अनोखी पहल सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र बना आर्कषण का केन्द्र

धमतरी। जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर एक अनोखी पहल की गई है। यहां "BaLA (Building as Learning Aid)" कॉन्सेप्ट पर आधारित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए गए हैं, जो अब पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन रहे हैं। आकर्षक रंग-रोगन, दीवारों पर शैक्षणिक चित्र और खेल-आधारित सीखने की सामग्री से ये केंद्र बच्चों के लिए जीवंत पाठशाला बन गए हैं। बीलएलए कॉन्सेप्ट के तहत भवन को ही सीखने का माध्यम बनाया जाता है। इन नवाचारों से बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और बौद्धिक विकास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है।

क्या-क्या बनाया गया है, दीवारों पर वर्णमाला, अंक और आकृतियां, रंग-बिरंगे तरीके से स्थानीय चित्रकथाएं, रचनात्मक पेंटिंग से सीख रहे बच्चे, फर्श पर पजल जैसी चीजें जिससे खेल-खेल में सीख सकें, खिड़की-दरवाजों तक में जोड़-घटाना सीखने के लिए बॉल लगे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में निर्मित और निर्माणाधीन सभी आंगनबाड़ी भवनों में बीएएलए कॉन्सेप्ट अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से गुणवत्ता और तय समयसीमा में निर्माण पूरा करने पर जोर दिया गया है। प्रदेश के सभी निर्माण कार्यों को 15 मार्च 2026 तक प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के कंडेल नवागांव में तैयार की गई मॉडल आंगनबाड़ी में बच्चों की ऊंचाई के अनुसार झरोखे, कस्टमाइज्ड टाइल्स, दीवारों पर शैक्षणिक लेखन तैयार किए गए हैं। सुरक्षित और आकर्षक वातावरण बनाने की कोशिश है जिससे यहां बच्चे अब दिलचस्पी के साथ पढ़ने आते हैं।

शादी समारोह में भोजन खाने के बाद ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत

गरियाबंद। गरियाबंद जिले से फूड पॉइजनिंग का सनसीखेज मामला सामने आया है, जहां दो ग्राम पंचायतों के 44 ग्रामीण अचानक बीमार पड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार, ग्रामीण शादी के चौथिया कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम में भोजन करने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। बताया जा रहा है कि गांव वापस लौटने के बाद ग्रामीणों को उल्टी-दस्त की शिकायत शुरू हुई। ग्राम पंचायत आमदी (द) के आश्रित मोहलाई के 17 ग्रामीण और ग्राम पंचायत दर्रीपारा के बोइरगांव के 27 ग्रामीण फूड पॉयजनिंग के शिकार हुए हैं।

दोनों ग्रामों के कुल मिलाकर अब तक 44 ग्रामीण बीमार बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। उपस्वास्थ्य केंद्र कोसमी में शिविर लगाकर सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्राथमिक उपचार के साथ आवश्यक दवाइयां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांवों में पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सीएमओ वीएस नवरत्न ने बताया कि मामले की सूचना के बाद डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों का दल कोसमी सेक्टर में ड्यूटी पर लगाया गया है। पीड़ितों का उपचार किया जा रहा है। अब तक 40 से ज्यादा लोगों का उपचार किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है।

धर्मांतरण के खिलाफ विधायक भावना बोहरा की पहल

- संस्कृति गौरव सम्मेलन में 165 लोगों ने की घर वापसी, छूने पैर पखारकर किया स्वागत

कवर्धा। जिले के पंडरिया क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर राजनीति और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। पंडरिया की विधायक भावना बोहरा इस विषय पर लगातार मुखर रुख अपनाए हुए हैं। रविवार को पंडरिया विकासखंड के आदिवासी ग्राम कुलहीडोंगरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान करीब 165 लोगों ने पुन: अपने मूल धर्म में वापसी की। बताया जा रहा है कि अब तक विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से 500 से अधिक लोग सनातन धर्म में लौट चुके हैं। ग्राम कुलहीडोंगरी में आयोजित 'संस्कृति गौरव सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह' में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम का माहौल पारंपरिक और सांस्कृतिक रंग में रंगा नजर आया। विधायक भावना बोहरा ने धर्म वापसी करने वाले सभी लोगों का पारंपरिक रीति-रिवाज से पैर पखारकर और नारियल भेंट कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया। आयोजकों के अनुसार, इस पहल को क्षेत्र में सांस्कृतिक अस्मिता, परंपरा और सामाजिक एकजुटता के संरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बोहरा ने धर्म परिवर्तन कराने में कथित रूप से सक्रिय एजेंटों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के सीधे-साधे लोगों को लालच, प्रलोभन या अंधविश्वास में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराना स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी ने किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाया है, तो उनकी धर्म वापसी सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें सामाजिक सम्मान के साथ पुन: जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक एकता और परंपराओं के संरक्षण पर भी जोर दिया गया।

सतनामी समाज ने जातिगत भेदभाव के लगाए आरोप

- रिसाली नगर निगम मेयर शशि सिन्हा पर जातिगत टिप्पणी करने का गंभीर आरोप लगा है.जिसे मेयर ने राजनीति से प्रेरित बताया है.

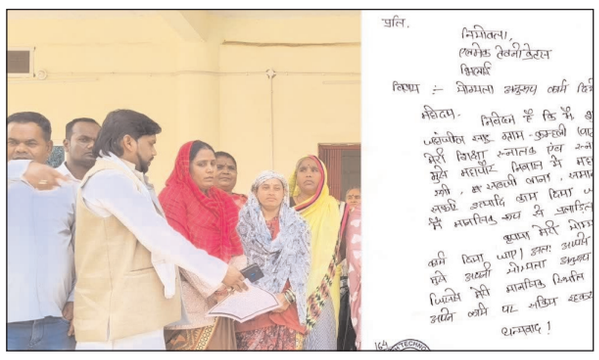

भिलाई। रिसाली नगर निगम के मेयर पर जातिगत टिप्पणी करने का गंभीर आरोप लगा है। ये आरोप मेयर के घर पर सफाई का काम करने वाले कर्मचारियों ने लगाए हैं। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि मेयर शशि सिन्हा और उनके परिजन घर पर काम करने के दौरान अमानवीय बर्ताव करते हैं।कई बार उन्हें जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित किया जाता है।

मेयर शशि सिन्हा के खिलाफ उनके घर पर काम करने वाले तीन सफाई कर्मी वेद बाई साहू, नेमा साहू और शुभम साहू ने ठेका एजेंसी को लिखित में आवेदन देकर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। शिकायत में सफाईकर्मियों ने कहा है कि उनकी गैर मौजूदगी पर किसी दूसरे को मेयर के घर पर यदि काम करने के लिए भेजा जाता है तो मेयर उन्हें जातिगत टिप्पणी करके काम करने से मना कर देती है।साथ ही साथ कुछ विशेष वर्ग के लोगों को घर में घुसने तक से मना कर दिया जाता है।अब सतनामी समाज मेयर के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कर्मचारियों ने काम बंद कर मेयर निवास का घेराव भी किया था। वहीं निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को हटाने का आदेश उनकी ओर से नहीं दिया गया। उनके अनुसार, कर्मचारी ठेका एजेंसी के हैं और उन्हें हटाने का निर्णय एजेंसी का है।वहीं कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्होंने योग्यता के मुताबिक काम नहीं करवाने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में सफाई एजेंसी के डायरेक्टर जहीर खान का कहना है कि कर्मचारियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें अमानवीय व्यवहार और निजी कार्य करवाने के आरोप शामिल थे। लिखित शिकायत के आधार पर ही कर्मचारियों को हटाया गया है। वहीं सुपरवाइजर ने भी माना है कि महपौर अमानवीय व्यवहार करती है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कठौतिया उपार्जन केंद्र में स्टॉक में भारी कमी की शिकायत

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जिले के कठौतिया धान उपार्जन केंद्र में धान के स्टॉक में भारी कमी और अनियमितता का गंभीर मामला सामने आया है। रिकॉर्ड के अनुसार केंद्र से अब भी 360 क्विंटल धान का उठाव शेष है, लेकिन मौके पर निरीक्षण के दौरान केवल 150 बोरी धान ही उपलब्ध पाया गया। उपलब्ध धान की गुणवत्ता और भंडारण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली, जिससे रख-रखाव में लापरवाही की आशंका और गहरा गई है। मामले ने तब तूल पकड़ा जब गोयल राइस मिल के संचालक संतोष गोयल ने इस विसंगति को लेकर जिला कलेक्टर, खाद्य अधिकारी और जिला विपणन अधिकारी को लिखित शिकायत दी। शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। समिति प्रबंधक बलराम सिंह से जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने के बजाय टालमटोल भरा उत्तर दिया। इससे संदेह और गहरा गया है कि कहीं न कहीं गंभीर चूक हुई है।

पानी बचाओ, बानी बचाओ अभियान, वैभव शिव पांडेय ने की अगुवाई

कवर्धा। छत्तीसगढ़ में मोर चिन्हारी के तहत पत्रकार वैभव शिव पांडेय ने पानी बचाओ, बानी बचाओ जनजागरुकता अभियान का आगाज किया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत की गई है। विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर पत्रकार वैभव शिव पांडेय ने बांकी स्थिति हॉफ नदी के उद्गम से इसकी शुरुआत की। दूसरे दिन यह यात्रा पंडरिया में समाप्त हुई। पंडरिया में पदयात्रियों का स्थानीय नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने जल स्रोतों के संरक्षण और मातृभाषा के संवर्धन की आवश्यकता पर जोर दिया। अभियान से जुड़े संयोजक डॉ. वैभव बेमेतरिहा ने कहा कि आज विश्वभर में जल संकट गहराता जा रहा है और कई मातृभाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे समय में समाज को अपनी नदियों और भाषा दोनों के प्रति सजग रहना होगा। गर्मी के मौसम में गांव और शहरों में जल संकट विकराल रूप ले लेता है. कई नदियां अब केवल बरसाती स्वरूप में सिमटती जा रही हैं, जिनमें हॉफ नदी भी शामिल हैं।

रिकॉर्ड गुम होने से आजीवन कारावास निरस्त-एचसी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी फैसला देते हुए आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया है और मामले में पुन: परीक्षण (री-ट्रायल) का आदेश दिया है। यह मामला उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने हत्या के आरोपी सरगुजा जिले के झिरमिट्टी निवासी लक्ष्मण राम नामक अभियुक्त से जुड़ा हुआ है। उसे सत्र न्यायालय, अंबिकापुर द्वारा हत्या (धारा 302) के आरोप में दोषी ठहराया गया था। आरोपी ने इस निर्णय के विरुद्ध वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने लखन राम को दी गई आजीवन कारावास की सजा को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि ट्रायल कोर्ट का मूल रिकॉर्ड गुम हो चुका है और अपील की सुनवाई बिना पूर्ण रिकॉर्ड के संभव नहीं है। अपील की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड गुम हो गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर रिकॉर्ड के पुनर्निर्माण का प्रयास किया गया, लेकिन गवाहों के बयान और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके।

युवक ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश

बिलासपुर। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कतियापारा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे पुलिस की तत्परता और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान अभय पांडेय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, अभय ने अचानक खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाकर युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तनाव में था। पारिवारिक विवाद को घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। अभय की पत्नी पिछले दो महीनों से उससे अलग रह रही थी। इसके अलावा युवक के शराब के नशे में विवाद करने की भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले एक महीने से काम पर भी नहीं जा रहा था।

जुआ अड्डे पर पुलिस की दबिश, जुआरी फरार नगदी जब्त

कांकेर। नरहरपुर क्षेत्र के ग्राम साईमुण्डा के जंगल-पहाड़ी में संचालित जुआ अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 11 मोटरसाइकिल, नगदी और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। हालांकि अंधेरे और जंगल की आड़ लेकर जुआरी मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, नरहरपुर थाना अंतर्गत चौकी दुधावा पुलिस को 20 फरवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम साईमुण्डा के जंगल-पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग संगठित रूप से जुआ खेल रहे हैं। सूचना की तस्दीक के बाद चौकी प्रभारी के निर्देश पर पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही जुआरी अपने-अपने वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल में भाग निकले। पुलिस ने मौके की घेराबंदी कर तलाशी ली, जहां से 11 मोटरसाइकिल, 650 रुपये नगद, 52 पत्ती ताश तथा अन्य सामग्री बरामद की गई।

देवी और माला राजी रेड्डी जैसे शीर्ष माओवादी नेताओं के आत्मसमर्पण के साथ नक्सलवाद मुक्त होने की राह पर बढ़ा देश

नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि करीब साठ से बासठ वर्ष का देवजी तेलंगाना के जगत्याल जिले के कोरुतला कस्बे के अंबेडकर नगर का निवासी है। दलित माला परिवार से आने वाले देवजी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही कट्टर वामपंथी विचारधारा की ओर रुख कर लिया था। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद से आई एक खबर ने दशकों से चल रहे माओवादी आंदोलन की कमर तोड़ कर रख दी है। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के शीर्ष कमांडर और प्रमुख रणनीतिकार टिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी तथा वरिष्ठ नेता मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम का आत्मसमर्पण उस अभियान की निर्णायक कड़ी बन गया है, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य के साथ शुरू किया था। हम आपको बता दें कि करीब साठ से बासठ वर्ष का देवजी तेलंगाना के जगत्याल जिले के कोरुतला कस्बे के अंबेडकर नगर का निवासी है। दलित माला परिवार से आने वाले देवजी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही कट्टर वामपंथी विचारधारा की ओर रुख कर लिया था। 1982 में वह रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा था। उसी दौर में करीमनगर जिले में आरएसयू और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं और एक मामले में उसका नाम आरोपी के रूप में सामने आया। 1983 में उसने सीपीआई एमएल पीपुल्स वार

ग्रुप का दामन थामा और भूमिगत हो गया। 1983 से 1984 के बीच वह गढ़चिरोली दलम का सदस्य रहा। 1985 में एरिया कमेटी सदस्य बना और 2001 में केंद्रीय समिति में जगह पाई। 2016 में उसे केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रभारी बनाया गया। देवजी को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के गठन का श्रेय दिया जाता है। वह संगठन की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो का सदस्य रहा तथा दक्षिण भारत जोन और सेंट्रल रीजनल ब्यूरो में सैन्य रणनीति का मुख्य मार्गदर्शक बना। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 2010 के दंतेवाड़ा हमले सहित कई बड़े हमलों की साजिश से उसका संबंध रहा है। उस पर एक से ढाई करोड़ रुपये तक का इनाम घोषित था। मई 2025 में सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजु की मौत के बाद माना जा रहा था कि देवजी ने संगठन की कमान संभाली। ऐसे समय में उसके आत्मसमर्पण ने संगठन के नेतृत्व को लगभग शून्य में ला खड़ा किया है। वहीं मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम लगभग 76 वर्ष का अनुभवी माओवादी नेता है। वह पेद्दापल्ली जिले के मुथारम मंडल के सथराजपल्ली गांव का निवासी है। 1975 में उसने नक्सली आंदोलन का रास्ता चुना और संगठन में विभिन्न अहम पदों पर रहा। उसके सिर पर भी एक करोड़ रुपये का इनाम था। राजी रेड्डी कई नामों से जाना जाता रहा और संगठन के केंद्रीय समिति सह पोलित ब्यूरो सदस्य के रूप में सक्रिय था। वह उन अंतिम शीर्ष नेताओं में था जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को थी। उसके साथ सोलह अन्य कैडर का आत्मसमर्पण माओवादी ढांचे के तेजी से सिमटते दायरे का संकेत है। हम आपको बता दें कि 17 फरवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नाम्बी और करेंगुट्टा पहाड़ियों में सीआरपीएफ के नेतृत्व में केजीएच 2 नाम से व्यापक अभियान शुरू हुआ था। खुफिया ब्यूरो और विशेष खुफिया शाखा ने परिवार और परिचितों के जरिये भी दबाव बढ़ाया। तेलंगाना के डीजीपी बी शिवाधर रेड्डी ने 15 फरवरी को खुले मंच से भूमिगत नेताओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी और राज्य की सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन योजना के तहत मदद का आश्वासन दिया था। बताया जाता है कि पिछले दो दिनों से देवजी और राजी रेड्डी पुलिस के संपर्क में थे। अंतत: रविवार तड़के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में विशेष खुफिया ब्यूरो के समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जाता है कि अक्टूबर 2025 में तेलंगाना के ही मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू ने गढ़चिरौली में 60 कैडर के साथ आत्मसमर्पण कर अस्थायी रूप से सशस्त्र संघर्ष त्यागने और युद्धविराम की बात कही थी। उसके रुख का कुछ वरिष्ठ नेताओं ने विरोध किया और माना जाता है कि देवजी सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के पक्ष में था। यह वैचारिक विभाजन संगठन को भीतर से कमजोर करता रहा। अब जब स्वयं देवजी ने हथियार डाल दिए तो यह संकेत है कि जमीन पर हालात बदल चुके हैं। देखा जाये तो पिछले एक वर्ष में देशभर में 2793 कैडर ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 1590 केवल बस्तर क्षेत्र से थे। 2025 में 1040, 2024 में 881, 2023 में 376 और 2022 में 496 आत्मसमर्पण दर्ज हुए। केवल तेलंगाना में पिछले दो वर्षों में 588 माओवादी नेता और कैडर सामान्य जीवन में लौटे हैं। हम आपको याद दिला दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट ऐलान किया था कि 31 मार्च तक देश से माओवादी उग्रवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। उनका यह बयान जमीनी हकीकत पर आधारित दिखता है। तीन वर्षों में व्यापक अभियान, सटीक खुफिया समन्वय, राज्यों के बीच तालमेल और पुनर्वास नीति के संयोजन ने माओवाद की रीढ़ तोड़ दी है।

संक्षिप्त समाचार

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

की अध्यक्षता में सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक श्री धरम लाल कौशिक, विधायक श्री धर्मजीत सिंह, विधायक श्री अजय चंद्राकर सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए अधिकारियों ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से

सोमवार को विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में राज्य प्रशासनिक सेवा तथा एलाइड सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह जनसेवा के व्यापक अवसरों और जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त श्री तीर्थराज अग्रवाल, सुश्री लीना कोसम, श्री बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, श्री सुमित अग्रवाल, श्री संदीप कुमार अग्रवाल, श्री आशीष कुमार टिकरिहा, श्री ऋषभ पाराशर एवं श्री तरुण किरण उपस्थित थे।

पॉवर कंपनी डंगनिया औषधालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के डंगनिया औषधालय द्वारा विद्युत कर्मियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर मे तीनों कंपनियों जनरेशन , ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के कर्मियों ने ऑख,नाक एवं कान के विशेषज्ञों से परामर्श एवं जॉच की सुविधा प्राप्त की। डंगनिया औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एच.एल पंचारी ने बताया कि शिविर में बीपी,शुगर,हार्टरेट एवं वरिष्ठ मरीज आमतौर पर सुनने में कमी ,साइनस की समस्या, गले मे संक्रमण जैसी समस्याओं के लिए परामर्श एवं जॉच की सुविधाओं का लाभ लिए। विद्युत कंपनी के अधिकारी,कर्मचारी,पेंशनर्स एवं आश्रित परिवरजनों को निःशुल्क परीक्षण की सुविधा प्राप्त हुई।यह शिविर में डॉ निलिसाी एवं डॉ तोमन कन्द्रा ने सेवाएं दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ इंदू साहू उपस्थित थीं।

दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनी द्रोणिका के कारण हुई हल्की वर्षा

रायपुर । एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है, इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढने और उसके बाद यह मुड़कर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तरफ अगले 48 घंटे में जाने की संभावना चलते राजधानी में सोमवार सुबह से बादल छाए रहे। सुबह 11.30 बजे के करीब अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश हुई। जो राहगीरों को भीगने से बचने जगह तलाशने मजबूर कर दिया। इस बेमौसम बदलाव का मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाएं हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश में आज कल एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है।

विधानसभा के सदस्यों के लिए ब्रह्मा भोजन का आयोजन सुंदर और प्रेरणादायी परंपरा : साय

कैबिनेट मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष और विधायक भी रहे मौजूद

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज नया रायपुर स्थित शांति सरोवर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानित सदस्यों के लिए प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नेह मिलन एवं ब्रह्मा भोजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने ब्रह्माकुमारी बहनों के स्नेह, आत्मीयता और सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि बहनों के प्रेम और आदर से हम सब अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बड़े स्नेह के साथ विधानसभा के सदस्यों के लिए ब्रह्मा भोजन का आयोजन एक सुंदर और प्रेरणादायी परंपरा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा समाज में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मिक शांति के प्रसार की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शांति सरोवर और शांति शिखर जैसे आध्यात्मिक केंद्रों में सदैव सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। संस्था का 137 से अधिक देशों में विस्तार होना अत्यंत सुखद और प्रेरक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अनेक

जनकल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में जनजागृति लाने का कार्य कर रहा है। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में संस्था की भूमिका उल्लेखनीय है। जनजातीय क्षेत्रों में भी संस्था द्वारा सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों से स्थानीय लोगों को व्यापक लाभ मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ब्रह्माकुमारी बहनों के अतिथि बने और पवित्र ब्रह्म भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित कैबिनेट मंत्रीगण और सभी विधायकगणों ने भी ब्रह्म भोजन का आनंद लिया। कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने मुख्यमंत्री एवं विधानसभा के सभी सदस्यों को माउंट आबू आने का आग्रह किया, जिसे मुख्यमंत्री श्री साय ने सहर्ष स्वीकार करते हुए वहां आने की सहमति दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक श्री धरमलाल कौशिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्रह्माकुमारी परिवार की ओर से मृत्युंजय भाई, आत्म प्रकाश भाई, हेमलता दीदी, लता दीदी, आशा दीदी, सरिता दीदी एवं सविता दीदी सहित अन्य सदस्य कार्यक्रम में सहभागी रहे।

बजट के एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का बड़ा बयान, कहा-

इस बार भी बजट से नहीं कोई उम्मीद : भूपेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट पेश करने से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक तरफ राज्यपाल के अभिभाषण के ठीक दूसरे दिन बजट पेश करने पर आपत्ति जताई, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं होने का आरोप मढ़ते हुए बजट को लेकर नाउम्मीदी जताई है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सरकार बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन बजट रख रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा गिर रही है। थकी, झुकी सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। इस बार भी बजट से कोई उम्मीद नहीं है। ट्रंप के भाषण से पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के बजट में क्या है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गलगोटियास यूनिवर्सिटी में चीनी रोबोट

विवाद पर कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक, गुरु कुत्ता खोजने का काम कर रहे थे। अब देशभर में चीनी कुत्ते की चर्चा चल रही है। कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने के लिए शर्टलेस हो गए। खुद नग्न प्रदर्शन दिल्ली में किए थे, तब खुद की बोली बातें याद नहीं आई। राहुल गांधी और 25 सांसदों को गोली मारने की बात कहा जाता है। तब मुंह में क्या दही जमा हुआ था, तब क्यों कुछ नहीं बोला।

वहीं होली पर शराब दुकान खुले रहने के सवाल पर मंत्री रामविचार नेताम पर भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश की इज्जत उतारने में लगी हुई हैं। होली के दिन शराब दुकान खोलेंगे तो कपड़ा उतरेगा ही। उन्होंने कहा कि हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। देश की इज्जत तार-तार बीजेपी कर रही है। हमारे देश का फैसला 7 समंदर पार बैठा ट्रंप कर रहा है।

वहीं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा नामांकन के लिए नामों को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि यह फैसला हाईकमान करेगा। अन्य साथियों को मौका मिलना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी नाम तय कर हाईकमान को भेजेगी।

सालभर जेल में बिताने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे कवासी लखमा

रायपुर। शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सालभर जेल में बिताने के बाद पहली बार सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। विधानसभा में पहुंचने के बाद लखमा ने कांग्रेस-भाजपा विधायकों से मुलाकात की, भाजपा विधायकों ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि शराब घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर हुए कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह ने कुछ शर्तों के साथ सत्र में शामिल होने की अनुमति दी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ। रमन सिंह ने उन्हें अंतरिम जमानत और विधानसभा की प्रक्रियात्मक शर्तों पालन करने का निर्देश देते हुए अनुमति दी गई है। क्योंकि, अभी जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है, उसकी जांच अभी जारी है। ऐसे में फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के सभी आदेशों और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा। विधानसभा सत्र के दौरान कवासी लखमा किसी भी तरह की स्पीच नहीं दे सकेंगे। वहीं सार्वजनिक बयानबाजी या अपने केस से जुड़े मामलों पर भी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। कवासी उपस्थिति केवल बजट सत्र तक ही सीमित रखी गई है, वह किसी और कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे। यही नहीं कवासी लखमा बजट सत्र के दौरान वह अपने निवास क्षेत्र का दौरा भी नहीं कर सकेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान कवासी लखमा को अपने आने और जाने की पूरी जानकारी विधानसभा सचिव के देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कवासी लखमा को दी गई अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाएगी। हालांकि, कवासी लखमा बजट सत्र के दौरान अपने हिस्से की चर्चा में भाग लें सकेंगे।

इतिहास से प्रेरणा लेकर ही सशक्त भविष्य का निर्माण संभव : संस्कृति मंत्री

- शौर्य और पराक्रम की जीवंत गाथा 'जाणता राजा' के समापन समारोह में शामिल हुए राजेश अग्रवाल

रायपुर। राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक साइंस कॉलेज ग्राउंड में छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग द्वारा आयोजित विश्वविख्यात महानाट्य 'जाणता राजा' का भव्य समापन समारोह अत्यंत उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर तथा आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा भी उपस्थित थे।

छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्वितीय शौर्य, रणनीति, राष्ट्रभक्ति और लोक-कल्याणकारी शासन की गाथा पर आधारित इस ऐतिहासिक महानाट्य ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। भव्य मंच सज्जा, सजीव अभिनय, प्रभावशाली प्रकाश एवं ध्वनि संयोजन तथा ऐतिहासिक दृश्यों की जीवंत प्रस्तुति ने मानो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को साकार कर दिया। महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित 'जाणता राजा' केवल एक

सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि राष्ट्रगौरव और स्वाभिमान की प्रेरक गाथा है। इस विश्वप्रसिद्ध नाट्यकृति की संकल्पना और प्रस्तुति सुप्रसिद्ध रंगकर्मी बाबासाहेब पुरंदरे द्वारा की गई थी, जिसने दशकों से देश-विदेश में दर्शकों को इतिहास से जोड़ा है।

संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जाणता राजा केवल एक नाटक नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की उस अमर गाथा का सजीव दर्शन है, जिसने हमें स्वराज, स्वाभिमान और सुशासन का मार्ग दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। उनके आदर्श हमें साहस, संगठन और राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आयोजनों का होना हमारे लिए गौरव का विषय है। राज्य सरकार संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के आयोजन हमारी नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं।

मंत्री श्री अग्रवाल ने आयोजन की सफलता के लिए छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग, कलाकारों, तकनीकी टीम तथा सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी राज्य में ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित कर सके। 'जाणता राजा' जैसे भव्य ऐतिहासिक मंचन न केवल सांस्कृतिक चेतना को जागृत करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई दिशा देते हैं। रायपुर में इस आयोजन ने प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं में इतिहास के प्रति नई जिज्ञासा और गर्व की भावना उत्पन्न की। समापन अवसर पर पूरा परिसर जय भवानी, जय शिवाजी के उद्घोष से गूंज उठा, जिसने वातावरण को राष्ट्रभाव से ओतप्रोत कर दिया।

रायपुर में पहली मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग बनकर तैयार

रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ती वाहनों की संख्या और पार्किंग की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने महानगरों की तर्ज पर पहला मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग तैयार कर लिया है। यह पार्किंग निगम मुख्यालय परिसर में बनाई गई है। इस अत्याधुनिक पार्किंग सिस्टम को एक सप्ताह के भीतर शुरू भी कर दिया जाएगा। फिलहाल इसमें नगर निगम की गाड़ियां ही खड़ी की जाएंगी।

बता दें कि निगम मुख्यालय परिसर में बनाई गई यह पार्किंग करीब 20 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार हुई है, जहां एक समय में 12 कारों को पार्क करने की सुविधा होगी। पूरी तरह से तैयार हो चुके इस पार्किंग सिस्टम में हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया गया है, जिससे कम जगह में अधिक वाहनों को सुरक्षित तरीके से खड़ा किया जा सकेगा।

नगर निगम के अधीक्षक अभियंता इमरान खान ने बताया कि मैकेनाइज्ड पार्किंग पूरी तरह बनकर तैयार है और एक सप्ताह के भीतर इसे निगम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां केवल निगम की गाड़ियां ही पार्क की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से परिसर में जगह की बचत होगी और वाहन सुरक्षित भी रहेंगे। गौरतलब है कि निगम मुख्यालय परिसर के अलावा पंडरी स्थित महालक्ष्मी मार्केट के पास भी मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग तैयार की जा रही है, जिसकी क्षमता 16 कारों की होगी।

श्रमिक की बेटी डिंपल अब संस्कार सिटी स्कूल में संवार रही अपना भविष्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में आई क्रांति अब सुदूर अंचलों के गरीब और श्रमिक परिवारों के आंगन तक पहुँचकर उनके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल रही है। शासन की अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाने का संकल्प अब धरातल पर जीवंत होता दिख रहा है। इसी कड़ी में बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम बिलौरी के एक पंजीकृत श्रमिक नंदकिशोर कश्यप की सुपुत्री डिंपल कश्यप ने अपनी मेधा और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता का अध्याय लिख दिया है। डिंपल का चयन राज्य की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर राजनांदगांव के प्रतिष्ठित संस्कार सिटी स्कूल के लिए हुआ है, जो उनके परिवार के लिए किसी सुखद चमत्कार से कम नहीं है। यहां डिंपल कक्षा छठवीं में अध्ययन कर रही है और बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेगी। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने डिंपल की माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की पूरी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। इस निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के प्रावधान ने परिवार के सिर से आर्थिक चिंता का बोझ पूरी तरह हटा दिया है, जिससे अब डिंपल की प्रगति की राह में कोई बाधा नहीं आएगी।

विशेष शिविर में 401 दिव्यांगजन हुए लाभान्वित

राज्य में दिव्यांग सशक्तिकरण को नई गति, संवेदनशील पहल से लौटी मुस्कान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की समावेशी और संवेदनशील नीतियों का प्रभाव अब सुदूर वनांचलों तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में राज्यभर में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सुकमा जिले में आयोजित तीन दिवसीय विशेष दिव्यांग सशक्तिकरण शिविर में 401 दिव्यांगजनों को आधुनिक सहायक उपकरण प्रदान कर आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई गई।

सुकमा के शबरी ऑडिटोरियम में 20 से 22 फरवरी तक आयोजित इस शिविर में कोंटा, छिंदगढ़ और सुकमा विकासखंड के हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उन्हें आवश्यक उपकरण मौके पर ही उपलब्ध कराए गए। यह शिविर केवल वितरण कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन और सम्मानजनक जीवन की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बना।

शिविर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर सहित विभिन्न सहायक उपकरण तैयार कर वितरित किए गए। वर्षों से बैसाखियों के सहारे चल रहे कई हितग्राहियों को जब आधुनिक कृत्रिम अंग मिले, तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और नई उम्मीद साफ झलक रही थी।

ट्राइसिकल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, छड़ी, स्टिक और बैसाखी जैसे उपकरण शिविर स्थल पर ही प्रदान किए गए। आर्टिफिशियल कैलिपर्स के लिए माप लेकर शीघ्र वितरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

समाज कल्याण विभाग की नोडल अधिकारी सुश्री मधु तेता ने बताया कि शिविर में 213 दिव्यांगजनों के प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन भी लिए गए, ताकि वे राज्य शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। यह पहल दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा है कि राज्य का कोई भी नागरिक अपनी शारीरिक बाधा के कारण अवसरों से वंचित न रहे। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए विभागीय योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। सुकमा का यह शिविर राज्य स्तर पर दिव्यांग सशक्तिकरण के व्यापक अभियान की कड़ी है।

अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि

- कल्याणपुर-लटोरी-दतिमा-सलका मार्ग का होगा सुदृढ़ीकरण ,40.93 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी नीति के अनुरूप क्षेत्र में आधारभूत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से जिला सूरजपुर अंतर्गत कल्याणपुर-लटोरी-दतिमा-सलका (मुख्य जिला मार्ग) के विभिन्न खंडों में सड़क

सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

लगभग 29 किलोमीटर लंबाई में प्रस्तावित इस कार्य के लिए 40.93 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह मार्ग क्षेत्र के अनेक ग्रामों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिसके उन्नयन से आवागमन अधिक सुगम, सुरक्षित एवं तीव्र होगा। इससे ग्रामीण अंचलों का जिला मुख्यालय एवं अन्य प्रमुख स्थलों से बेहतर संपर्क स्थापित होगा।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सड़क केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि विकास की जीवनरेखा है। सुदृढ़ सड़क संपर्क से किसानों को अपनी उपज समय पर बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों तक सुगमता से पहुंच सुनिश्चित होगी तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक त्वरित पहुंच संभव हो सकेगी। साथ ही व्यापार, लघु उद्योग एवं स्थानीय रोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता एवं समावेशी विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। अधोसंरचना विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से चरणबद्ध रूप से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बस्तर मण्डल, जगदलपुर

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-
निविदा डाऊनलोड करने की अंतिम तिथि:- 09/03/2026

स.क्र.	नि.आ.सू.क्र./ नि.आ.सू. दिनांक	सिस्टम निविदा क्रमांक निविदा का क्रम	कार्य का नाम	कार्य की अनुमाति लागत (रूपये लाख में)
01	02	03	04	05
	233/2025-26 दिनांक 19/02/2026	185902 (प्रथम आमंत्रण)	माँ दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में ए.एम.सी. कार्य का निर्माण कार्य। (वॉल रिपेयरिंग एवं पेंटिंग, प्रथम टर्मिनल भवन के गार्ड रूम का रिपेयरिंग, क्रेश गेट रिपेयरिंग, पाकिंग एरिया के 24 गेट रिपेरिंग, फायर स्टेशन शेड, फ्लोरिंग एरिया के रिपेयरिंग एवं रनवे क्रेक फिलिंग कार्य)	72.38
02	234/2025-26 दिनांक 19/02/2026	185903 (प्रथम आमंत्रण)	माँ दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में ए.एम.सी. कार्य का निर्माण कार्य। (क्रांकीट पेवमेंट, ड्रेन (ल. 597.00 मी.) ग्रेनेटी वर्क, पाईप क्लर्वट, एल्युमिनियम वर्क, लेवलिंग वर्क, सेनेटरी फिटिंग, रूफ रिपलेसमेंट, आर. सी.सी. बैरक का रिनोवेशन कार्य)	191.41

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
बस्तर मुडल जगदलपुर

जी- 252606835/6

बांग्लादेश की नई सरकार में हिंदू मंत्रियों की आमद

डॉ. रमेश ठाकुर

पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तारिक रहमान के रूप में नई सरकार शपथ ले चुकी है। खास बात ये है रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार में दो हिंदू सांसदों को मंत्री बनाया गया है। उनके इस निर्णय को भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से बिगड़े संबंधों को सुधारने की पहल के रूप में समूची दुनिया देख रही है। इस कदम से चीन-पाकिस्तान चिड़े भी हैं। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश भारत या उनसे वास्ता रखने लोगों को तवज्जो दे। लेकिन, तारिक रहमान ने उनके नापाक मंसूबों को धता बताते हुए, बड़ी सूझबूझता से कदम आगे बढ़ाया। बीते कुछ महीनों में 11 हिंदुओं के साथ हुई निर्मम बर्बरता ने बांग्लादेश की न सिर्फ थू थू करवाई, बल्कि दशको से मधुर संबंधों को भी पटरी से उतार दिया था। इसको लेकर दोनों मुल्कों में तल्खियां बनी हुई थीं। रहमान जानते हैं अगर माहौल ऐसा ही बरकरार रहा, तो रिश्तो की दूरियां घटने वाली नहीं? ऐसी अखरती दुश्वारियों पर गौर करते हुए ही रहमान ने अपनी कैबिनेट में हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों को अहम औहदे सौंपे ताकि रिश्तों में फिर से नरमी लाई जा सके। भारत ने भी उनके निर्णय को सराहा है। गौरतलब है कि तारिक रहमान के आगाज से पूर्व बांग्ला-हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार हुए हैं और हो भी रहे हैं? ऐसी निंदनीय घटनाओं को तत्काल प्रभाव से रोकने की चुनौती तारिक रहमान के सामने अभी भी खड़ी है। हालांकि, रोकने के लिए वह अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री रहमान सबसे पहले पूर्व की अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस के अटपटे और संबंध बिच्छेद भरे निर्णयों की समीक्षा करेंगे। उनका झुकाव भारत को परेशान करने वाली पाकिस्तान-चीन की संयुक्त खुराफाती नीतियों की ओर ज्यादा रहा था। रहमान अच्छे से समझते हैं कि जबतक मोहम्मद यूनुस कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने की हर संभव कोशिशें कीं। कुछ उन्होंने की और कुछ दूसरे देशों ने करवाई? दूसरे देश कौन से हैं जिनके नाम लेने की शायद जरूरत नहीं? सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारतीय हुकूमत का साथ लेकर और अपनी कैबिनेट में अल्पसंख्यक हिंदू मंत्रियों की आमद के साथ बांग्लादेश में अगले पांच सालों तक समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर जब उनकी पार्टी बीएनपी चुनावों में जीती तो सबसे पहले वह अपने धुरविरोधी विपक्षी नेता और जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान के बिना बुलाए, ढ़लती शाम के बाद उनके आवास पहुंच गए। चुनावी गुस्सेबाजियों के इतर उनसे नई सरकार में सहयोग की गुजारिश करी। विपक्षी नेता ने भी राजनीतिक दुश्मनी छोड़कर उनका गर्मजोशी से अपने घर पर स्वागत किया। दरअसल, इस तरह की खूबसूरत परंपरा का प्रचार-प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए, कि चुनाव बाद विपक्ष से सत्ता पक्ष को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये उन देशों के लिए सीख भी है जहां पक्ष-विपक्ष आपस में अनैतिक कुकर्मों की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। रहमान उस विपक्षी नेता के घर भी पहुंचे जिनकी पार्टी चुनावों में तीसरे स्थान पर रही। नेशनल सिटीजन पार्टी के नाहिद इस्लाम को भी गले लगाया और बांग्लादेश के विकास में उनसे भी सहयोग मांगा। राजनीति में ऐसी तस्वीरों का दिखना दुर्लभ होता है, लेकिन बांग्लादेश में दिखी। रहमान की जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उन्हें भाई बताना और उनकी जीत की खुशी में फूल-मिठाईयां को ढाका भेजना भी धूमिल संबंधों में रस भरने जैसा कहा जाएगा। साथ ही रहमान के शपथ में भारत सरकार की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पहुंचना भी सुखद और नए संबंधों में नए सिरे से गढ़ने जैसा है।

भारत का एआई नेतृत्व तकनीक एवं मानवीय मूल्यों का संगम बने

ललित गर्ग

दिल्ली इन दिनों केवल भारत की राजनीतिक राजधानी भर नहीं, बल्कि उभरती तकनीकी चेतना का वैश्विक केंद्र बनी हुई है। 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब प्रयोगशालाओं या कॉरपोरेट दफ्तरों तक सीमित तकनीक नहीं रही, बल्कि वह विकास की नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में अग्रसर है। दुनिया के विभिन्न देशों, तकनीकी कंपनियों, शोध संस्थानों और नीति-निर्माताओं की उपस्थिति ने इस सम्मेलन को वैश्विक विमर्श का मंच बना दिया है। यह आयोजन इस तथ्य का उद्घोष है कि भारत केवल उपभोक्ता राष्ट्र नहीं, बल्कि एआई युग का नेतृत्वकर्ता बनने की तैयारी में है। आज विश्व जिस तकनीकी संक्रमण से गुजर रहा है, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णायक भूमिका निभा रही है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, शासन और आर्थिक विकास-हर क्षेत्र में एआई समाधान की नई संभावनाएँ खोल रहा है। ऐसे समय में भारत का दृष्टिकोण केवल तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं, बल्कि वह इसे मानव-केंद्रित विकास के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि तकनीक का अंतिम लक्ष्य मानवता की सेवा होना चाहिए, न कि केवल लाभ और वर्चस्व की दौड़।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। यदि इस ऊर्जा को गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और डाटा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाए तो भारत एआई अनुसंधान और नवाचार में विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सकता है। विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो वास्तविक शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, न कि केवल झूठे दावों और विज्ञापन के बल पर प्रतिष्ठा अर्जित करने का प्रयास करें। शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता ही उस आधारशिला को मजबूत करेगी जिस पर भारत का एआई भविष्य खड़ा होगा। यह सवाल उठाया जा रहा है कि भारत आज व्यवहार में एआई व रोबोटिक्स के अनुसंधान में कहां खड़ा है? आखिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नीति-नियंताओं ने यह क्यों नहीं सोचा कि चीन निर्मित एक रोबोट को अपनी

उपलब्धि बताने से देश की प्रतिष्ठा को आंच आएगी? अब यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि उसने रोबोट के निर्माण का दावा नहीं किया। वहीं दूसरी ओर उन सरकारी अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जिन्होंने बिना जांच-पड़ताल के विश्वविद्यालय को एआई समिट में स्टॉल लगाने की अनुमति क्यों दी। निश्चित रूप से भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक व रोबोटिक उत्पादन के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है। युवा शक्ति के देश भारत ने एआई के क्षेत्र में अमेरिका व चीन के बाद अपना तीसरा स्थान बनाया है। जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं ने भी की है। लेकिन एक विरोधाभासी हकीकत यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश है, जहां श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई की भूमिका क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती है। रोगों की प्रारंभिक पहचान, सटीक निदान, दवाओं के शोध और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार में एआई नई संभावनाएँ लेकर आया है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहाँ स्वास्थ्य संसाधनों का असमान वितरण है, वहाँ एआई आधारित समाधान दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर सेवाएँ पहुँचाने में सहायक हो सकते हैं। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान, मृदा विश्लेषण, फसल प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन में एआई किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने का माध्यम बन सकता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी आज मानवता के सामने विकराल रूप में उपस्थित है। चरम मौसम की घटनाएँ, जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन विकास की गति को प्रभावित कर रहे हैं। एआई आधारित मॉडलिंग और डेटा विश्लेषण से प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और टिकाऊ नीतियों का निर्माण संभव है। यदि भारत इन क्षेत्रों में एआई का प्रभावी उपयोग करता है तो वह वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए एक मार्गदर्शक मॉडल प्रस्तुत कर सकता है।

शासन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी एआई पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण, भ्रष्टाचार पर अंकुश, नीति निर्माण में डेटा-आधारित निर्णय और वित्तीय समावेशन के विस्तार में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल होंगी, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी मजबूत होगा। आर्थिक दृष्टि से एआई नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और विनिर्माण क्षेत्र में नई ऊर्जा भर सकता है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। किन्तु इस उजाले के साथ कुछ गहरी छायाएँ भी हैं। एआई के बढ़ते प्रभाव से रोजगार संरचना में परिवर्तन स्वाभाविक है। अनेक पारंपरिक नौकरियाँ समाप्त हो सकती हैं और नई कौशल-आधारित नौकरियों की माँग बढ़ेगी। यदि कौशल विकास और पुनर्प्रशिक्षण पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो असमानता और बेरोजगारी की समस्या गहरा सकती है। इसी प्रकार डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, डीपफेक और निगरानी जैसे प्रश्न लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती बन सकते हैं। तकनीक का दुरुपयोग सामाजिक विभाजन और सूचना के दुष्प्रचार को बढ़ा सकता है।

इसलिए आवश्यक है कि एआई के विकास के साथ नैतिक ढाँचे और नियामक व्यवस्था भी सुदृढ़ हो। भारत को ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जिसमें नवाचार की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संतुलन बना रहे। मानवता केंद्र में का सिद्धांत केवल नारा न बने, बल्कि नीति और व्यवहार में परिलक्षित हो। एआई का उपयोग यदि समावेशी विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए किया जाए तो यह तकनीक समाज के कमजोर वर्गों के लिए अवसरों का द्वार खोल सकती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन और अमेरिका एआई के क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत के सामने चुनौती है कि वह इस दौड़ में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विशाल बाजार उसे एक अलग सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यदि वह अनुसंधान में निवेश, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दे तो वह एआई के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए सस्ती, सुलभ और मानव-केंद्रित तकनीक उपलब्ध कराकर भारत एक नैतिक नेतृत्व स्थापित कर सकता है।

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सम्मेलन केवल विचारों का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि भविष्य की संरचना का प्रारूप है। यहाँ से निकले संकल्प यदि नीति और क्रियान्वयन में रूपांतरित होते हैं तो भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा सकेगा। यह अवसर है कि हम एआई को केवल आर्थिक लाभ का साधन न मानें, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन और मानव कल्याण के माध्यम के रूप में देखें। आज जब दुनिया में मानवीय मूल्यों का क्षरण चिंता का विषय है, तब भारत के पास अवसर है कि वह तकनीक और नैतिकता के समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करे। एआई का विकास यदि करुणा, समावेशन और सतत विकास के आदर्शों के साथ हो तो यह मानवता के लिए वरदान सिद्ध होगा। भारत को अपने युवाओं, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई की यात्रा मानवता के उत्थान की यात्रा बने, न कि केवल प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की।

निस्संदेह, ऐसे वक्त में जब कृषि से लेकर चिकित्सा तक और उत्पादन के क्षेत्र में एआई व रोबोटिक्स की दखल बढ़ रही है, प्रचुर श्रमशक्ति की उपलब्धता के बावजूद भारत को समय के साथ कदमताल करनी होगी। हमें एआई व रोबोटिक्स को अपनाना ही होगा। लेकिन सावधानी के साथ ताकि यह नौकरी खाने वाला बनने के बजाय नौकरी देने वाला बने। समय की पुकार है कि हम तकनीकी प्रगति को राष्ट्रीय संकल्प में बदलें। शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास और नैतिक नेतृत्व के सहारे भारत एआई युग में एक नई पहचान गढ़ सकता है। यदि हम चुनौतियों को स्वीकार कर दूरदर्शिता से आगे बढ़ें तो यह युग भारत के लिए केवल तकनीकी उन्नति का नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व और मानवीय पुनर्जागरण का युग सिद्ध हो सकता है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

यदि सूक्ष्म दृष्टि से सोने के संघीभूत परभाणुओं का विश्लेषण किया जाय तो उपर्युक्त विज्ञान के अनुसार सोने में वस्तुत: अग्नि चाँद और जल के गुणों का ही विमिश्रण पाया जाता है। न्याय-शास्त्र में सोने को तैजस पदार्थ माना है। यह अग्नि ताप से पिघल कर द्रवीभूत हो जाता है, इसका स्वाभाविक स्पर्श अनुष्णाशीत है और तैजस पदार्थ होने के कारण इसमें भास्वरशुक्लता का समावेश स्वीकार किया जाता है। सो सोने में द्रवत्व जलतत्त्व का विकार है, घनीभाव चन्द्रमा के दिव्य हिम का प्रतिफल है और देदीप्यमान भास्वरता अग्नितत्त्व का गुण है यद्यपि इसमें न्यूनाधिक उपर्युक्त तीनों गुणों का समावेश पाया जाता है। तथापि हमारे पूर्वकथनानुसार इसमें अधिक भाग आग्नेय वाष्प का ही मिला है, अतएव प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इस नियम के अनुसार पूर्वाचार्यों ने इसे तैजस पदार्थों में ही परिगणित किया है। श्रीवेदव्यास जी ने महाभारत मैं स्पष्टतया इसे अग्नि का ही विकार स्वीकार किया है, यथा -

अग्नेरपत्यमेतद्व सुवर्णमिति धारणा ।

(महाभारत- अनुशासन 85 । 147)

अर्थात् सुवर्ण अग्नि से उत्पन्न हुआ पदार्थ है, ऐसी धारणा है। कदाचित् कोई सज्जन हमारे इस वैज्ञानिक भाव को कोरी कल्पना ही न समझ बैठें ! एवं किसी के हृदय में उक्त आख्यायिका के प्रधान पात्र शिव, विष्णु और मोहिनी आदि का अभिप्राय क्रमश: (सोम-) चन्द्रमा, (अग्नि) आग्नेय वाष्प और पृथ्वी का आदिम पिण्ड किन प्रमाणों के आधार पर अवलंबित है - ऐसी आशङ्का न बनी रहे !- एतदर्थ हम वैदिक साहित्य से ऐसे प्रमाण उद्धृत करते हैं कि जो हमारी रूपक कल्पना का समर्थन करते हुए इस आख्यान के मध्यवर्ती शिव विष्णु शब्दों के हमारे प्रकट किये अर्थों का भी सोहलों आने अनुमोदन करते हो, तद्यथा- **क्रमश: ..**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

दिलीप कुमार पाठक

भारत की आर्थिक प्रगति के पीछे उन हजारों हाथों का योगदान है, जो देश के राजस्व को मजबूत करने के लिए दिन-रात काम करते हैं। इन्हीं प्रयासों को सम्मान देने और आम जनता को कर व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 24 फरवरी को देश में एक विशेष अवसर के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। यह समय हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसी दिन साल 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाया गया था। भले ही आज के दौर में टैक्स की प्रणालियां बदल गई हों और जीएसटी ने एक बड़ा स्थान ले लिया हो, लेकिन देश की तरक्की में उत्पाद शुल्क का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। एक आम नागरिक के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर टैक्स चुकाने से उसे क्या मिलता है। इसका जवाब बहुत ही सरल और सुंदर है। जब देश की फैक्ट्रियों में सामान बनता है और उस पर सरकार को शुल्क मिलता है, तो वही पैसा घूमकर समाज के कल्याण के लिए वापस आता है। हमारे गाँव और शहरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें, अंधेरे को दूर करती बिजली की रोशनी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के आधुनिक हथियार, यह सब उसी कर के पैसे से संभव हो पाता है जो एक जिम्मेदार उद्यमी और नागरिक द्वारा चुकाया जाता है। इस प्रकार, कर का भुगतान करना केवल एक कानूनी काम नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर राष्ट्र की सेवा करने जैसा है।

इसी संदर्भ में यह समझना भी जरूरी है कि एक मजबूत कर प्रणाली ही देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी खतरों से निपटने की शक्ति प्रदान करती है। जब सरकार के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, तभी नई तकनीकों और आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश किया जा सकता है। यह राजस्व ही है जो आपदाओं के समय राहत कार्य चलाने और देश के करोड़ों गरीब परिवारों तक मुफ्त राशन और जरूरी सुविधाएं पहुँचाने में मदद करता है। बिना मजबूत वित्तीय आधार के कोई भी देश अपने नागरिकों के सपनों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए, उत्पाद शुल्क केवल एक सरकारी उगाही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक सशक्त माध्यम भी है, जो उद्योगों से कर लेकर समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान में खर्च किया जाता है। समय के साथ सरकारी कामकाज के तरीकों में भी बड़ा बदलाव आया है। आज का दौर डिजिटल क्रांति का है और अब टैक्स चुकाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने या लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं रह गई है। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को इतना सरल और पारदर्शी बना दिया है कि कोई भी व्यापारी घर बैठे अपना हिसाब-किताब पूरा कर सकता है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, बल्कि व्यापार करने में भी आसानी हुई है। यह समय उन अधिकारियों और कर्मचारियों के परिश्रम को भी सलाम करने का है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि देश का खजाना सुरक्षित रहे और कहीं भी राजस्व की चोरी न हो। इसके साथ ही, हमें यह भी समझना होगा कि कर के माध्यम से एकत्र किया गया धन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ईंधन की तरह काम करता है।

अमेरिका के साथ समझौते को समझने की जरूरत

अजय शाह

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को देश में राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि इस समझौते के जरिये राष्ट्रीय हित का 'पूर्ण समर्पण' कर दिया गया है। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने भारत को चेतावनी दी कि भारत रूसी तेल खरीद बंद कर रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता कर रहा है।

यह व्यापारिक नजरिया सही नहीं है कि निर्यात पुरस्कार है और आयात एक तरह की कीमत जो अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। बुनियादी स्तर पर देखें तो अंतरराष्ट्रीय कारोबार में पुरस्कार है आयात यानी विदेश से होने वाली खरीद और भारतीय कंपनियों की उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि। हर व्यापार समझौते का मूल्य इस बात से आंका जाता है कि उससे भारतीय व्यापार गतिरोध में क्या कमी आएगी?

मध्यवर्ती वस्तुओं और मशीनरी पर ऊंचा शुल्क भारतीय कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ाने वाला है। गैर सक्षम घरेलू क्षेत्रों को संरक्षण देकर हम अप्रत्यक्ष रूप से सक्षम कंपनियों पर कर लगाते हैं। उदारीकरण को 'समर्पण' बताने वाली धारणा में यह माना जाता है कि यथास्थिति ही सबसे बेहतर थी। यह सच नहीं है।

यथास्थिति की काफी ऊंची कीमत चुकानी होती है। कम प्रतिस्पर्धा वाला माहौल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण की प्रक्रिया को बाधित करता है और देश की आर्थिक वृद्धि को भी। अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर शुल्क समाप्त करने या घटाने की प्रतिबद्धता उत्पादकता को झकझोरने वाला है। जब भारतीय निर्माता अमेरिका से उच्च-प्रौद्योगिकी मशीनरी, मध्यवर्ती इनपुट और घटक बिना अत्यधिक शुल्क की रुकावट के आयात कर सकते हैं, तो उनकी लागत कम हो जाती है।

अर्थशास्त्रियों के एक सिद्धांत के अनुसार आयात पर कर वास्तव में निर्यात पर कर के समान है।

आयात बाधाओं को कम करके हम भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधार रहे हैं। इससे भारतीय श्रम और पूंजी का आवंटन गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों से हटकर उन क्षेत्रों में होता है जिसमें भारत वास्तव में अच्छा है, और इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होती है।

खाद्य पदार्थों पर शुल्क प्रतिगामी है। इसका असमान रूप से असर गरीबों पर पड़ता है। ये लोग भोजन के शुद्ध खरीदार होते हैं। राजनीतिक विचारकों को भूस्वामी किसान परिवारों के समूह के आकार की तुलना उन गरीब लोगों की संख्या से करनी चाहिए जो भोजन खरीदते हैं। खाद्य शुल्क बड़े भू-स्वामित्व को उसी तरह लाभ पहुंचाते हैं जैसे कच्चे माल पर सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य करते हैं। गरीबों के लिए बेहतर पोषण से मिलने वाले सकारात्मक बाह्य प्रभावों का पूरा तर्क खाद्य व्यापार बाधाओं को कम करने से मिलने वाले लाभों में बदल जाता है। अब जो समस्या सामने आएगी वह है श्रेष्ठ आर्थिक ज्ञान (मसलन तीन हालिया व्यापार समझौतों यानी अमेरिका,यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में) और बहुपक्षीय स्तर पर लागू पुराने भारतीय समाजवाद के बीच असंगति।

भारत लंबे समय से विश्व व्यापार संगठन में फंसा रहा है। विश्व व्यापार समझौते यानी डब्ल्यूटीए में विकास हेतु निवेश सुविधा (आईएफडी) समझौते पर विचार कीजिए। इस पहल का उद्देश्य निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पारदर्शिता में सुधार करना है। फिर भी,भारत ने इसे अपनाने पर रोक लगा दी है। इसी समय, अमेरिका के साथ संयुक्त वक्तव्य भारत की पूंजी और प्रौद्योगिकी आकर्षित करने की मंशा को उजागर करता है, जिसमें ऊर्जा,विमान और प्रौद्योगिकी उत्पादों सहित 500 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामान खरीदने की इच्छा भी शामिल है। द्विपक्षीय स्तर पर सक्रिय रूप से निवेश आमंत्रित करना, जबकि बहुपक्षीय स्तर पर संरचनात्मक रूप से निवेश सुविधा का विरोध करना, असंगत है।

डिजिटल क्षेत्र में भी ऐसा ही पाखंड है। द्विपक्षीय समझौता संवेदनशील तकनीक, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अधोसंरचना आदि के क्षेत्र में सहयोग पर जोर देता है। दूसरी तरफ, डब्ल्यूटीओ में भारत लगातार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क के स्थायी स्थगन को अपनाने का विरोध करता रहता है। हम डिजिटल अर्थव्यवस्था का हार्डवेयर यानी डेटा-सेंटर उपकरण और चिप्स आयात करना चाहते हैं, जबकि उस सॉफ्टवेयर और डेटा प्रवाह पर कर लगाने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो हार्डवेयर को उपयोगी बनाता है।

वर्तमान समझौता एक अंतरिम समझौता है। इसमें बहुत सारे इरादे शामिल हैं लेकिन वे कानूनी बाध्यताएं नहीं हैं। ट्रंप के दौर में यह जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा, हमें इस पर अधिक सोचना होगा कि किसके पास किस पर नियंत्रण है। पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता केंद्रीय नियोजन की ओर वापसी है। सरकारें सामान नहीं खरीदते, कंपनियां खरीदती हैं। हम यह आशा ही कर सकते हैं कि अधिकारी खरीद लक्ष्य निर्धारित न करें।

गैर शुल्क बाधाओं पर दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रतिबद्धता चिकित्सा उपकरणों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मानकों और परीक्षण आवश्यकताओं पर केवल छह माह की समीक्षा के लिए है। समीक्षा सुधार नहीं है। एक उच्च-गुणवत्ता वाला द्विपक्षीय व्यापार समझौता नियामक सामंजस्य के लिए विशिष्ट समयसीमा वाली बाध्यकारी व्यवस्था की मांग करता है। चिकित्सा उपकरणों या उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार में टकराव का बिंदु अक्सर शुल्क नहीं होता, बल्कि मनमाने परीक्षण और प्रमाणन मानक होते हैं,जो वास्तविक संरक्षणवाद और कानून के शासन की अनुपस्थिति के रूप में कार्य करते हैं।

इसी तरह, डिजिटल अर्थव्यवस्था को केवल अस्पष्ट सहयोग से अधिक की आवश्यकता है। भारत ने डिजिटल व्यापार पर नियमों को लेकर वार्ता करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन अभी तक सीमा-पार डेटा प्रवाह या अनिवार्य सोर्स कोड खुलासे पर बाध्यकारी प्रावधानों पर सहमति नहीं दी है। आधुनिक मुक्त व्यापार समझौते में, जैसे यूएस-मेक्सिको-कनाडा समझौता,ये मानक स्तंभ हैं।

इनके बिना तकनीकी साझेदारी घरेलू नियामक मनमानी और ट्रंप की अप्रत्याशित प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों के प्रति असुरक्षित रहती है। स्रोत के नियमों को लेकर भी कई बाधाएं हैं। जैसे-जैसे आपूर्ति श्रृंखलाएं चीन से अलग होती हैं, अमेरिका घुसपैठ करने वाली जांच की मांग करेगा। इससे भारतीय कंपनियों को उस पारदर्शिता और अनुपालन को स्वीकार करना होगा जो वे सामान्यत: नहीं करतीं। इसे लागू करने के लिए राज्य की क्षमता आवश्यक होगी। सत्यापन प्रक्रिया इंस्पेक्टर राज का अगला दौर नहीं बननी चाहिए, जिसमें विलंब, अनुपालन लागत और भ्रष्टाचार शामिल हों।

यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ एफटीए और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता मिलकर भारतीय उदारीकरण की एक अच्छी लहर निर्मित कर सकते हैं। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ समझौते जिस मैत्रीपूर्ण राजनीतिक वातावरण में किए गए हैं, उन्हें वास्तविक गहन समझौतों में बदलना आवश्यक है। हमें अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के दस्तावेज पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें भारतीय व्यापार बाधाओं का उल्लेख है।

आज का इतिहास

1893 अमेरिकी विश्वविद्यालय वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गयी।
1918 आर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया तीनो शहर को ट्रांसस्कोजेनियाई डेमोक्रेटिक संघीय गणराज्य के रूप में रूस से आजादी मिली।
1920 जर्मन वर्कर्स पार्टी की एक बैठक में, एडॉल्फ हिटलर ने पार्टी के 25-सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और पार्टी ने अपने नैमेटो नाजी पार्टी को बदल दिया।
1945 मिस्र और सीरिया ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1946 कर्नल जुआन पेरोन, राजनीतिककरण के संस्थापक जिन्हें पेरोनिज़्म के रूप में जाना जाता है, अर्जेंटीना के अपने पहले कार्यकाल के लिए चुने गए थे।
1948 फिल्म से लेकर राजनीति तक का सफर तय करने वाली जयललिता का जन्म हुआ।
1969 मरिनर 6 मार्स जांच संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू की गई।
1974 पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर बंगलादेश को मान्यता प्रदान की।
1989 यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 811 ने होनोलुलु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को छोड़ने के बाद एक अनियंत्रित नियंत्रण का अनुभव किया, नौ यात्रियों को मार डाला, जब उनकी सीटों को विमान से चूसा गया।
2003 चीन के जिजियांग प्रान्त में भीषण भूकम्प से 257 मरे।
2004 रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल कास्यानोव को उनके पद से हटाया।
2006 फिलीपीन के राष्ट्रपति ग्लोरिया मैकापगल-अरोयो ने एक संभावित सैन्य तख्तापलट करने की कोशिश में एक राज्य-आपातकाल की घोषणा की।
2008 फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिया, उनके भाई राउल कास्त्रो को सर्वसम्मति से चुना गया।
2010 जनरल मोटर्स से हथौड़ा खरीदने के लिए तेंगझोंग की बोली चीन के पीपुल्स रिपब्लिक के वाणिज्य मंत्रालय ने खारिज कर दी है।
2011 यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह ने देश के सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों को बचाने का आदेश दिया।
2011 लीबिया में, विरोधी गद्दाफी बलों ने त्रिपोली के पश्चिम में स्थित एक शहर जुआरा पर नियंत्रण पाने का दावा किया है।
2012 अपनी सरकार के भीतर एक शक्ति संघर्ष के बाद, हैती के प्रधान मंत्री गैरी कोनील ने इस्तीफा दे दिया।

एआई तकनीक में विश्व का नेतृत्व करेगा भारत

मनोज कुमार अग्रवाल

राजधानी नई दिल्ली के में आयोजित पांच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का शनिवार को समापन हो गया, लेकिन इस सम्मेलन की सफलता ने भारत को ग्लोबल साउथ में अग्रणी नेतृत्वकारी देश के रूप में स्थापित कर दिया है। इस शिखर सम्मेलन में 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया जाना न केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि है, बल्कि यह भारत की उस सोच की वैश्विक स्वीकृति भी है, जो तकनीक को मानव कल्याण से जोड़कर देखती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मानव-केंद्रित एआई दृष्टिकोण औउखर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को जिस व्यापक वैश्विक समर्थन मिला है, वह बताता है कि दुनिया तकनीकी प्रगति को केवल आर्थिक लाभ लाभ के नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के संदर्भ में भी देखना चाहती है।21 फ़रवरी को 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट डिक्लेरेशन का समर्थन किया। इनमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इस डिक्लेरेशन में किए गए सारे कमिटमेंट स्वैच्छिक हैं, यानी ये उन देशों की इच्छा पर निर्भर है कि वे इसके मुताबिक़ कितना काम करते हैं।

इस डिक्लेरेशन में देशों ने इस समिट में सात चक्र में हुई चर्चाओं का संज्ञान लिया और कहा कि वे स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में हुए एआई समिट से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के विकास में अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान भी किया जाएगा।

आपको पता हो कि 88 देशों और दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। यह सिद्धांत केवल एक सांस्कृतिक वाक्यांश नहीं, बल्कि तकनीकी विकास के लिए एक नैतिक दिशा है। ऐसे समय में जब एआई को लेकर विश्व में प्रतिस्पर्धा, नियंत्रण और प्रभुत्व की राजनीति हावी है, भारत ने समावेशी और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर एक संतुलित विकल्प दिया है। समिट के दौरान एआई क्षेत्र में 250 अरब डॉलर के संभावित निवेश का भरोसा जताया जाना भारत की आर्थिक क्षमता और नीति स्थिरता पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। यह निवेश केवल पूंजी का प्रवाह नहीं, बल्कि नवाचार, रोजगार और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार का अवसर है। साथ ही यह फंडिंग दर्शाती है कि दुनिया भारत को एआई के भविष्य के केंद्र के रूप में देख रही है। भारत पहले से ही आईटी और डिजिटल सेवाओं में वैश्विक केंद्र रहा है। अब एआई में नेतृत्व का अर्थ है कि उच्च कौशल वाले रोजगार, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा और वैश्विक कंपनियों के लिए अनुसंधान एवं विकास का प्रमुख केंद्र बनना। यदि यह निवेश सही दिशा में लागू हुआ, तो भारत न केवल उपभोक्ता बल्कि एआई समाधानों का प्रमुख उत्पादक भी बन सकता है। एआई की तीन प्रगति ने कई नैतिक और सुरक्षा संबंधी प्रश्न भी खड़े किए हैं, जिसमें डेटा गोपनीयता, एल्गोरिदमिक पक्षपात, साइबर सुरक्षा और रोजगार पर प्रभाव जैसी चिंताएं गंभीर हैं।

भारत एआई इम्पैक्ट समिट का एक प्रमुख उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान खोजना था। भारत ने जिस प्रकार विकासशील देशों की आवाज को मंच दिया, वह अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह तथ्य कि पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित हुआ, अपने आप में ऐतिहासिक है। लंबे समय तक तकनीकी विमर्श विकसित देशों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा है। भारत ने इस परंपरा को बदलते हुए यह दर्शाया कि नवाचार और नीति-निर्माण में विकासशील देशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ग्लोबल साउथ के कई देश डिजिटल अवसंरचना के विस्तार और डेटा आधारित शासन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर आदि पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा चुका है। अब एआई के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का साझा मॉडल विकसित किया जा सकता है, जिससे छोटे और मध्यम आय वाले देशों को लाभ हो। भारत की युवा आबादी और तकनीकी प्रतिभा उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। विश्व की अग्रणी टेक कंपनियों में भारतीय मूल के विशेषज्ञों की मजबूत उपस्थिति यह दर्शाती है कि देश में गणित और इंजीनियरिंग की ठोस परंपरा है। चुनौती यह है कि यह प्रतिभा देश के भीतर शोध और उत्पाद विकास में रूपांतरित हो। जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स में बढ़ती फंडिंग एक सकारात्मक संकेत है। निवेशकों का बढ़ता भरोसा बताता है कि भारतीय उद्यमी केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि उत्पाद-निर्माता बनने की ओर अग्रसर हैं। हालांकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचने के लिए दीर्घकालिक और धैर्यपूर्ण निवेश आवश्यक होगा। अनुसंधान-आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, उद्योग और सरकार के बीच मजबूत सहयोग की जरूरत है। एआई अब प्रयोगशाला की अवधारणा नहीं, बल्कि व्यावसायिक वास्तविकता बन चुका है। वित्त, बीमा, दूरसंचार, ई-कॉमर्स और विनिर्माण क्षेत्रों में एआई आधारित विश्लेषण और स्वचालन से उत्पादकता में वृद्धि देखी जा रही है। यदि यह प्रवृत्ति स्थायी बनती है, तो एआई भारत की आर्थिक वृद्धि दर में प्रत्यक्ष योगदान दे सकता है। विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में एआई के प्रयोग से सामाजिक प्रभाव की व्यापक संभावनाए हैं। कृषि में सटीक खेती, स्वास्थ्य में रोग-पूर्वानुमान, शिक्षा में अनुकूलित शिक्षण और पर्यावरण में जलवायु विश्लेषण ये सभी क्षेत्र भारत के विकास एजेंडा से सीधे जुड़े हैं। यदि एआई समाधान ग्रामीण भारत तक पहुंचते हैं, तो समावेशी विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति संभव है। भारत की बहुभाषी सांस्कृतिक संरचना एआई के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। यदि भारत भारतीय भाषाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट और बहुभाषी मॉडल विकसित करता है, तो वह न केवल घरेलू बाजार को सशक्त करेगा, बल्कि वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए समाधान भी निर्यात कर सकेगा। मीडिया और रचनात्मक उद्योगों में एआई आधारित सामग्री निर्माण, अनुवाद और वॉयस इंटरफेस से नए आर्थिक अवसर उत्पन हो सकते हैं। एआई अवसंरचना के विस्तार के साथ ऊर्जा और जल-उपयोग जैसे प्रश्न भी जुड़े हैं। डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या पर्यावरणीय दबाव उत्पन कर सकती है। अत: एआई विकास को अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता नीतियों के साथ संतुलित करना आवश्यक संतुलित कर है। तकनीकी नेतृत्व तभी टिकाऊ होगा जब वह पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। साथ ही, एआई के कारण पारंपरिक नौकरियों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कौशल उन्नयन को नई पीढ़ी को उभरती तकनीकों के अनुरूप तैयार करना अनिवार्य है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत केवल डिजिटल उपभोक्ता रष्ट नहीं, बल्कि वैश्विक तकनीकी विमर्श का नेतृत्व करने में सक्षम है। समिट में शामिल देशों के द्वारा निवेश का भरोसा भारत के लिए अवसर के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी लेकर आया है। एआई का युग मानव इतिहास के सबसे परिवर्तनकारी चरणों में से एक हो सकता है। यह तकनीक अवसर भी है और चुनौती भी। नई दिल्ली में हुए इस शिखर सम्मेलन ने यह संकेत दिया है कि भारत इस परिवर्तन को दिशा देने के लिए तैयार है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का सिद्धांत यदि केवल नारा न रहकर नीति और व्यवहार का हिस्सा बनता है, तो एआई का भविष्य अधिक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी हो सकता है। अब अब दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि भारत और उसके साझेदार इस ऐतिहासिक सहमति को ठोस कदमों में कैसे बदलते हैं। यदि यह प्रयास सफल होता है, तो 2026 का यह सम्मेलन वैश्विक तकनीकी शासन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में याद किया जाएगा।

आपको बता दें कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित पांच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट शुक्रवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान अमेरिका, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने 'नई दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट' पर हस्ताक्षर किए।इस समझौते को भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है। पिछले साल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने यूरोप के नियमों का हवाला देते हुए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन नई दिल्ली में भारत सभी देशों को एक मंच पर लाने में सफल रहा। भारत का लक्ष्य एआई का लोकतंत्रीकरण करना है, ताकि यह तकनीक कुछ बड़ी कंपनियों या सीमित लोगों तक ही सीमित न रहे।यह घोषणा पत्र एआई के भविष्य के लिए एक दिशा तय करता है और साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है।इस के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को स्वीकार करना ही होगा।

चीन को जिसका डर था, अमेरिका ने भारत के साथ वही कर दिया!

अभिनय आकाश

दिल्ली में ऐसा फैसला हुआ है, जिसने एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने एक बड़े रणनीतिक कदम के तहत अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि इससे बीजिंग की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस गठबंधन का मकसद है सेमीकंडक्टर,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और एडवांस टैक्स सप्लाई चेन को सुरक्षित और चीन पर निर्भरता से मुक्त होना।

पैक्स सिलिका अमेरिकी सरकार का एक प्रमुख रणनीतिक फ्रेमवर्क है। इसके तहत अमेरिका अपने विश्वसनीय साझेदार देशों के साथ तकनीक और औद्योगिक इकोसिस्टम का साझा नेटवर्क विकसित कर रहा है। इसे वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पर चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

इसका मुख्य उद्देश्य एआई और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वैश्विक सप्लाई चेन तैयार करना है। तकनीकी विकास के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स की निर्बाध आपूर्ति इस रणनीति का अहम हिस्सा है। दिसंबर में बने इस समूह में जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इस्राइल सहित कई देश शामिल है। अब भारत के औपचारिक रूप से जुड़ने के बाद इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई है।

भारत ऐसे समय इस पहल में शामिल हुआ है जब हाल के महीनों में भारत-अमेरिका संबंधों में ट्रेड डील और अन्य वैश्विक मुद्दों को लेकर कुछ असहजता देखी गई थी। हालाकि हाल ही में दोनों देशों के बीच एक अतरिम समझौते पर सहमति बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से द्विपक्षीय सहयोग, खासकर इमरजिंग टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, और गहरा होगा। चीन के दबदबे को संतुलित करने की रणनीति में भारत की भूमिका मजबूत होगी।

यह गठबंधन पूरी चिप निर्माण प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। यानी खदानों से निकलने वाले जरूरी खनिजों से लेकर चिप बनाने वाली फैक्टियों तक और उन डेटा सेंटर्स तक, जहां अडवास्ड चलाया जाता है- हर स्तर पर सुरक्षा और भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है।

हाई क्वालिटी चिप मैन्युफैक्चरिंग होगी। सप्लाई चेन विविधकरण होगा। टेक्निकल निवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही 6त्न डाटा सेंटर और एडवांस होंगे। मैन्युफैक्चरिंग में संयुक्त प्रोडक्शन बढ़ेगा। भारत में पहले से ही 10 सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित या प्रक्रिया में है। उम्मीद है कि जल्द भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन जल्दी ही शुरू करेगा। भारत में दो नैनोमीटर चिप डिजाइनिंग पर भी काम हो रहा है जो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में गिनी जाती है। इंडिया यूएस संबंधों पर भी पैक्स सिलिका का असर पड़ेगा। बता दें कि यह कदम प्रस्तावित इंडिया यूएस ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने इसे 21वीं सदी की आर्थिक और तकनीकी व्यवस्था को आकार देने वाला रणनीतिक गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा और अमेरिका की टेक्नोलॉजी क्षमता मिलकर विश्वसनीय एआई इकोसिस्टम तैयार कर सकती है। युवाओं और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसके साथ ही टैक सेंटर में नई नौकरियां आएंगी। विदेश निवेश बढ़ेगा। एआई और सेमीकंडक्टर में स्टार्टअप्स शुरू होंगे और इकोसिस्टम इससे मजबूत होगा। 47 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए यह एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स के खनन से लेकर उन्हें चिप्स में परिवर्तित करने और फिर डेटा सेंटर्स तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया इसमें शामिल है। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि अब हम पैक्स सिलिका का हिस्सा है। इससे हम इस महत्वपूर्ण सप्लाई चेन में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यह भारत के टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यक्रममें के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

ट्रंप के खिलाफ यूरोप में दिखावटी एकता की पड़ताल

एस प्रसन्नराजन

शुक्र है कि किसी भी फ्रांसीसी अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप के अत्याचार से एकजुट दुनिया की सोच को 9/11 की अपनी उस मशहूर पंक्ति 'आज हम सब अमेरिकी हैं' को 'आज हम सब अमेरिका-विरोधी हैं' जैसी कोई सुर्खी बनाकर पेश ?नहीं किया। इसके बजाय, ट्रंप की नीतियों से प्रभावित देशों में से एक, कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी नैतिकता और वाकपटुता से ट्रंप-पीड़ित उदारवादी विश्व की भावनाओं को हवा दी। उन्होंने न सिर्फ खुद को 'शक्तिहीनों' का प्रतिनिधि बताया, बल्कि वाक्लाव हवेल (चेक रिपब्लिक के पहले नेता) की शैली में असहमति की शक्ति का प्रदर्शन भी किया। हालांकि, इतने बड़े सिंहनाद तथा वेनेजुएला, ग्रीनलैंड व नाटो जैसे शब्दों के भू-राजनीतिक हिंसा का पर्याय बनने के बावजूद, ट्रंप के बेलगाम फैसलों के खिलाफ अब तक कोई ठोस वैश्विक दीवार खड़ी नहीं हो पाई है। बेशक, यूरोपीय राजधानियों में हमेशा की तरह हंगामे के स्वर सुनाई दिए हों, और हमने एकजुट होकर मुकाबला करने के नए इरादों के बारे में भी पढ़ा, पर नतीजा वही ढाक के तीन पात ही रहा। चाहे जो भी हो, ट्रंप के खिलाफ गुस्से ने दुनिया भर में अमेरिका-विरोध की अब तक की सबसे बड़ी लहर तो पैदा कर ही दी है, जिसे कई वैश्विक नेताओं का समर्थन भी मिलता दिख रहा है।

भारत भी इस लहर से अछूता नहीं था। ओबामा दौर के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की धूम मची, तो भारतीय दक्षिणपंथी, यह देखकर खुश थे कि एक और बाहरी व्यक्ति बड़ी-बड़ी व्यवस्थाओं से भिड़ रहा है, और यह भारतीय खेमा ट्रंप के वैश्विक प्रशंसकों की कतार में सबसे आगे था। ट्रंप ने भी भारत के दोस्त की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। ह्यूस्टन में मोदी के साथ उनकी साझा उपस्थिति इसका उदाहरण बनी। कुछ समय के लिए ही सही, ट्रंप भारत के स्वाभाविक सहयोगी भी बने। राष्ट्रीय रूढ़िवाद की बड़ी कहानी में, ट्रंप को हंगरी के विक्टर ओर्बन के साथ एक बेहद प्रभावशाली पात्र के रूप में देखा जा सकता था और भारतीय दक्षिणपंथियों में %मेक अमेरिका ग्रेट अगेन% (मागा) के कई जोशीले समर्थक भी थे। ऐसा लग रहा था, मानो ट्रंप ने प्रतीकों की तलाश में जुटी एक विचारधारा में राष्ट्रीय हित का एक और पहलू जोड़ दिया हो। उस समय हम सभी 'ट्रंपिस्ट' बन चुके थे, जहां अमेरिका-विरोध की कोई जगह नहीं थी। उस दौर में ऐसा होना ही सच्चा 'रूढ़िवाद' माना जाता था।

हालांकि, यह सब कुछ तब बदल गया, जब ट्रंप ने

टैरिफ हमले के साथ अमेरिका के राष्ट्रीय हित को फिर से परिभाषित किया। इस टैरिफ युद्ध को जीतने के लिए ट्रंप दृढ़संकल्पित भी थे, क्योंकि वह जानते थे कि एक सौदेबाज कोई भी युद्ध ऐसी दुनिया में ही जीत पाएगा, जो अंतरराष्ट्रीयता से ज्यादा लेन-देन को महत्व देती है। देखते ही देखते, तथाकथित भारतीय दक्षिणपंथी भी अचानक 'ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम' (ट्रंप विरोधी भावना) के शिकार हो गए और उन्होंने कुछ समय के लिए दबी हुई अमेरिका-विरोधी भावना को बाहर निकाल दिया। क्या यह उस तथाकथित बुद्धिजीवी समुदाय के अस्थिर वैचारिक मूल का मामला था, जिसने अपने विश्वास को उस सरकार की नीतिगत मजबूरियों पर निर्भर बना दिया, जिसका समर्थन करने के लिए वे मजबूर थे? या फिर ऐसा था कि अमेरिकावाद और अमेरिका-विरोधी भावना ऐसे आसान लेबल थे, जिन्हें सत्ता के बदलते मूड के साथ जोड़ा जा सकता था?

जैसे ही सरकार ने ट्रंप के साथ व्यापारिक समझौते पर मुहर लगाई, ऐसा लगा, मानो 'अमेरिका-विरोध' का सुर फीका पड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति को रातों-रात उन्हीं लोगों ने बुरा कहना बंद कर दिया, जो सोवियत युग के 'तीसरी दुनिया' वाले पुराने ढर्रे को पुनर्जीवित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि ट्रंप का अमेरिका तीखी आलोचना की आग से पूरी तरह बच गया, बल्कि सच यह है कि राजनीतिक मौसम बदलने के साथ अमेरिकावाद का उपसर्ग भले बदल गया हो, पर कुछ चीजें वैसी की वैसी ही रहीं।

इस बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में एक धुरी जो अडिग रही, वह थी मोदी सरकार। अपने कुछ दक्षिणपंथी बड़बोले समर्थकों के उलट, इसने कभी भी न तो खुद को अमेरिका-विरोधी भावना का समर्थक दिखाया और न ही बताया, यहां तक कि ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के भारत ने ट्रंप की दादागीरी का सामना अपने राष्ट्रीय सम्मान को बनाए रखते हुए किया, वह भी दुनिया के लिए अमेरिकी खतरे पर एकजुट हुई अंतरराष्ट्रीय आवाज में शामिल हुए बिना और अंतरराष्ट्रीय कानून पर घिसी-पिटी बातें किए बगैर। मोदी और ट्रंप ऐसे दो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो अपनी-अपनी शैली में खेल रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय हित को लेकर ऐसा नजरिया अपनाया कि अंतरराष्ट्रीयतावाद के पारंपरिक अमेरिकी आदर्श अचानक पुराने लगने लगे। उनके लिए, अमेरिका की ताकत को पूरी तरह समझने के लिए उनके जैसे राष्ट्रपति की जरूरत थी, जो अमेरिका को सबसे पहले और सबसे आगे रखता हो। वहीं दूसरी ओर, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो उदार लोकतंत्र में निस्संदेह सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं, धैर्यवान राष्ट्रवादी हैं, जो इतिहास की लंबी दिशा को ध्यान में रखकर खेल खेलते हैं, न कि सुर्खियों के लिए। मोदी, अपने ज्यादातर समर्थकों से अधिक समझदार निकले, और उन्होंने ट्रंप के कट्टर अमेरिकावाद को अमेरिका-विरोधी भावना से मिलाने से साफ इन्कार कर दिया। यूरोप में दूसरी जगहों पर, अपनी सांस्कृतिक जड़ों के बावजूद, ऐसे नेता अमेरिका-विरोधी भावना को बनाए हुए हैं, जिनके पैरों तले जमीन तेजी से खिसक रही है।

ट्रंप की अव्यवस्था के खिलाफ यूरोप में मेहनत से बनाई गई इस दिखावटी एकता का कोई व्यावहारिक मतलब नहीं है, क्योंकि यह राजनीतिक हताशा से उपजे 'अमेरिका-विरोध' के सिवा और कुछ नहीं है। भले ही 'ताकत' ट्रंप का पसंदीदा नीति बन गई हो, पर अमेरिका-विरोधी सोच के यूरोपीय समर्थकों ने कमजोरी को ही संस्थागत रूप दे दिया है। यूरोप की एकजुटता, भले ही वह ट्रंप को एक उत्प्रेरक के रूप में दरकिनार कर दे, फिर भी वास्तविक 'शक्ति' में तब्दील नहीं हो पाती और यह बात सिर्फ सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है। क्या यूरोपीय संघ सबसे ज्यादा विनियमित देशों के संघ का एक अच्छा उदाहरण नहीं है? आज इसका सामना एक ऐसे अमेरिका से है, जो परंपरा को तोड़कर, एक राजशाही अहंकार वाले राष्ट्रपति के अधीन आजादी को विनियमित करने का साहस कर रहा है।

यह एक असमान मुकाबला है, जहां यूरोप ज्यादा से ज्यादा एक वैचारिक बहस तो जीत सकता है, पर जमीन पर उसका कोई खास असर होने वाला नहीं है। शायद हम पुराने असहमति वाले माहौल में वापस लौट आए हैं, चाहे पूरब हो या पश्चिम, अमेरिका-विरोध की बातें तो की ही जा रही हैं। एक ऐसी विचारधारा, जिसे नागरिक समाजों और सांस्कृतिक विकल्प ने खारिज कर दिया है, के पास जीतने के लिए सिर्फ ट्रंप जैसा ही कोई अस्थायी मुद्दा बचा है।

चीन की नई कूटनीति या पुरानी चाल?

कांतिलाल मांडोत

हाल के वर्षों में उपग्रह तस्वीरों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह संकेत मिले हैं कि चीन अपने सामरिक ढांचे को तेजी से मजबूत कर रहा है। दक्षिण-पश्चिमी प्रांतों में पहाड़ों के भीतर बने बड़े-बड़े बंकर, भूमिगत सुरंगें और अत्याधुनिक सुविधाएं इस ओर इशारा करती हैं कि बीजिंग अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर चुपचाप काम कर रहा है। ऐसे समय में जब वह भारत के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने और सहयोग बढ़ाने की बात करता है, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या चीन वास्तव में भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है या यह उसकी रणनीतिक नीति का हिस्सा है।

इतिहास गवाह है कि भारत और चीन के संबंधों में विश्वास की कमी की जड़ें गहरी हैं। वर्ष 1962 में चीन द्वारा भारत पर किया गया हमला दोनों देशों के रिश्तों में एक स्थायी अविश्वास की दीवार खड़ी कर गया। उसके बाद से सीमा विवाद, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव और समय-समय पर होने वाली झड़पों ने यह स्पष्ट किया कि संबंधों में गर्मजोशी और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर है। चीन ने कई बार शांति और सहयोग की बात की, लेकिन समानांतर रूप से अपनी सैन्य और सामरिक ताकत को भी बढ़ाया।

चीन की विदेश नीति को समझने के लिए उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को देखना जरूरी है। वह

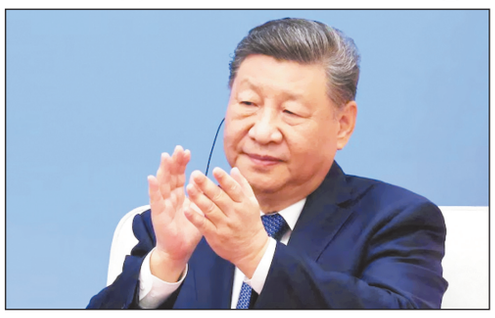

तात्कालिक भावनाओं के बजाय दशकों आगे की योजना बनाकर चलता है। उसकी प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विस्तार है। चाहे वह दक्षिण चीन सागर हो, ताइवान का मुद्दा हो या हिमालयी सीमा हर जगह उसकी नीति शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में झुकाने की रही है। ऐसे में यदि वह भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल करता है, तो यह केवल सद्भावना का परिणाम नहीं बल्कि एक सुविचारित रणनीति भी हो सकती है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में चीन कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक तनाव, तकनीकी प्रतिबंध और सामरिक प्रतिस्पर्धा ने उसे नए संतुलन की तलाश में डाल दिया है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति है। एशिया में स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भारत के साथ टकराव चीन के हित में नहीं है। इसलिए संभव है कि वह सीमित सहयोग और नियंत्रित प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाए, ताकि वह एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष से बच सके।

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि चीन की नीतियों में पारदर्शिता का अभाव रहा है। उसकी सैन्य तैयारियों और परमाणु ढांचे के विस्तार को लेकर अक्सर बाहरी दुनिया को सीमित जानकारी ही मिलती है। यदि उपग्रह तस्वीरों में दिखाई देने वाले निर्माण सचमुच सामरिक क्षमताओं के विस्तार का संकेत हैं, तो यह भारत सहित पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। एक ओर संवाद और व्यापार की बातें, दूसरी ओर पहाड़ों के भीतर बनते ठिकान यह दोहरी तस्वीर सहज भरोसा पैदा नहीं करती।

भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह चीन के इरादों को कैसे परखे। केवल बयानों के आधार पर विश्वास करना रणनीतिक भूल हो सकती है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संवाद के द्वार खुले रखने होंगे। कूटनीति में संतुलन और सैन्य तैयारी में सतर्कता दोनों समान रूप से जरूरी हैं। चीन के साथ संबंधों को पूरी तरह टकराव की दिशा में ले जाना भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि दोनों देश एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और परस्पर निर्भरता भी बढ़ी है।

चीन की नियति को समझने के लिए यह भी देखना होगा कि वह वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। उसकी बेल्ट एंड रोड पहल, तकनीकी निवेश और वैश्विक संस्थाओं में बढ़ती भूमिका इस दिशा का संकेत देती है।

क्या विपक्ष के पास नेतृत्व संकट? सामना के लेख में कई तीखे सवाल

पवन पांडेय

महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) ने बुधवार को दावा किया कि इंडिया ब्लॉक अब एक चौराहे पर खड़ा है, और उसे आंतरिक बहस से आगे बढ़कर यह तय करना होगा कि ममता बनर्जी, एमके. स्टालिन या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रीय संकट में उनका नेतृत्व करेगा या नहीं। महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चुनावों से पहले ब्लॉक और कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और नेतृत्व को लेकर चल रही बहसें एकता को कमजोर करने की धमकी दे रही हैं। सामना के संपादकीय में कहा गया कि गठबंधन के अंदर आपसी मतभेद और अंदरूनी लड़ाई बढ़ रही है। आने वाले राज्यों के चुनाव से पहले यह स्थिति विपक्ष की एकता को कमजोर कर सकती है। इसे फ्रेंडली फायर यानी अपने ही साथियों के बीच टकराव बताया गया। संपादकीय के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में गठबंधन के दल एक-दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस आमने-सामने हैं, वहीं केरल में लेफ्ट और कांग्रेस में भी मुकाबला है। इसके साथ महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर विभाजन से भाजपा को फायदा हुआ है। शिवसेना यूबीटी का कहना है संसद का हंगामा अलग है, लेकिन देश में लोगों की सोच बदल रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन को जल्द फैसला करना होगा कि उनका नेतृत्व कौन करेगा- ममता, स्टालिन या कोई तीसरा नेता? विपक्षी इंडिया गठबंधन के अंदर कई नेताओं ने अलग-अलग नाम आगे किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का समर्थन किया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सचिव रहे संजय बारू ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बेहतर राष्ट्रीय नेता बताया है। इनका कहना है कि गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए जल्द एक चेहरा तय करना जरूरी है। संपादकीय में कहा गया है कि कांग्रेस में भी अंदरूनी मतभेद दिख रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता अलग-अलग राय दे रहे हैं, इससे पार्टी की एकजुटता पर असर पड़ रहा है हालांकि, राहुल गांधी की लड़ने की भावना की तारीफ भी की गई। संपादकीय में यह भी कहा गया कि सरकार धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। इससे जनता की सोच प्रभावित हो रही है और विपक्ष को इसका जवाब देने के लिए मजबूत नेतृत्व चाहिए।

कैसे दक्षिणमुखी मकान में नहीं होता दक्षिण दोष

वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा के मकान को कुछ परिस्थिति को छोड़कर अशुभ और नकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है। दरअसल, हर दिशा में कोई न कोई ग्रह स्थित है जो कि अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। यह निर्भर करता है मकान के वास्तु, मुहल्ले के वास्तु और उसके आसपास स्थित वातावरण और वृक्षों की स्थिति पर।

प्रत्येक ग्रह का अपना एक वृक्ष होता है। जैसे चंद्र की शनि से नहीं बनती और यदि आपने घर के सामने चंद्र एवं शनि से संबंधित वृक्ष या पौधे लगा दिए हैं तो यह कुंडली में चंद्र और शनि की युति के समान होते हैं जो कि विषयोग कहा गया है। आओ जानते हैं कि कैसे दक्षिणमुखी मकान में नहीं होता दक्षिण दोष?

- यदि दक्षिणमुखी मकान के सामने द्वार से दोगुनी दूरी पर स्थित नीम का हराभरा वृक्ष है तो दक्षिण दिशा का असर कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा।
- यदि दक्षिणमुखी मकान के सामने मकान से दोगना बड़ा कोई दूसरा मकान है तो दक्षिण दिशा का असर कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा।
- दक्षिणमुखी मकान का दोष खत्म करने के लिए द्वारा के उपर पंचमुखी हनुमानजी का चित्र भी लगाना चाहिए।
- दक्षिण मुखी प्लाट में मुख्य द्वार आग्नेय कोण में बना है और उत्तर तथा पूर्व की तरफ ज्यादा व पश्चिम व दक्षिण में कम से कम खुला स्थान छोड़ा गया है तो भी दक्षिण का दोष कम हो जाता है।। बगीचे में छोटे पौधे पूर्व-ईशान में लगाने से भी दोष कम होता है।
- आग्नेय कोण का मुख्यद्वार यदि लाल या मरून रंग का हो, तो श्रेष्ठ फल देता है। इसके अलावा हरा या भूरा रंग भी चुना जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में मुख्यद्वार को नीला या काला रंग प्रदान न करें।
- दक्षिण मुखी भूखण्ड का द्वार दक्षिण या दक्षिण-पूरब में कतई नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम या अन्य किसी दिशा में मुख्य द्वार लाभकारी होता हैं।
- यदि आपका दरवाजा दक्षिण की तरफ है तो द्वार के ठीक सामने एक आदमकद दर्पण इस प्रकार लगाएं जिससे घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में बने। इससे घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के साथ घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक उर्जा पलटकर वापस चली जाती है।

कैसा होना चाहिए घर का मुख्य द्वार

घर के दरवाजे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार हम मकान खरीदते वक्त या बनवाते वक्त यह ध्यान नहीं देते हैं कि किस प्रकार के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। घर का मुख्य द्वार वास्तु अनुसार होता है तो कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बेहतर होगा कि दरवाजा शीशम या सागौन की लकड़ी और धातु का बना हो। दरजावा किसी भी प्रकार सा टूटा फूटा या तिरछा नहीं होना चाहिए। द्वार के खुलने बंद होने में आने वाली चरमराती ध्वनि स्वरवेध कहलाती हैं जिसके कारण आकस्मिक अप्रिय घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। आओ जानते हैं कि घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए।

- एक सीध में तीन दरवाजे नहीं होना चाहिए।
- दरवाजे के भीतर दरवाजा नहीं बनाना चाहिए।
- एक पल्ले वाला दरवाजा नहीं होना चाहिए। दो पल्ले वाला हो।
- ऐसा दरवाजा नहीं होना चाहिए जो अपने आप खुलता या बंद हो जाता हो।
- घर का मुख्य द्वार बाहर की ओर खुलने वाला नहीं होना चाहिए।
- कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनमें खिड़कियां होती हैं ऐसे दरवाजों में वास्तुदोष हो सकता है।
- मुख्य द्वार त्रिकोणाकार, गोलाकार, वर्गाकार या बहुभुज की आकृति वाला नहीं होना चाहिए।
- मुख्य दरवाजा छोटा और उसके पीछे का दरवाजा बड़ा नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाजा बड़ा होना चाहिए।
- घर के ऊपरी माले के दरवाजे निचले माले के दरवाजों से कुछ छोटे होने चाहिए।
- घर में दो मुख्य द्वार हैं तो वास्तुदोष हो सकता है। विपरीत दिशा में दो मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए।

क्या कोई युग लाखों वर्ष का होता है

युग क्या होता है इस संबंध में 5 तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। दूसरी बात यह कि भारत के धार्मिक इतिहास को युगों की प्रचलित धारण में लिखना या मानना कितना उचित है? जैसे कि श्रीराम जी त्रैता में और श्रीकृष्ण जी द्वापर में हुए थे। इस तरह तो इतिहास कभी नहीं लिखा जा सकता है। इतिहास को तो तारीखों में ही लिखना होता है और वह भी तथ्य और प्रमाणों के साथ। आओ जानते हैं कि युग की 5 मान्यताएं।

उल्लेखनीय है कि आपने सुना ही होगा मध्ययुग, आधुनिक युग, वर्तमान युग जैसे अन्य शब्दों को। इसका मतलब यह कि युग शब्द को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता रहा है। मतलब यह कि युग का मान एक जैसी घटनाओं के काल से भी निर्धारित हो सकता है। तो क्या यह सही है या कि युग की धारणा कुछ और ही है?

पहली मान्यता

युग के बारे में कहा जाता है कि 1 युग लाखों वर्ष का होता है, जैसा कि सतयुग लगभग 17 लाख 28 हजार वर्ष, त्रेतायुग 12 लाख 96 हजार वर्ष, द्वापर युग 8 लाख 64 हजार वर्ष और कलियुग 4 लाख 32 हजार वर्ष का बताया गया है।

दूसरी मान्यता

एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष का माना गया है। इस मान से चारों युग की एक चक्र 5 हजार वर्षों में पूर्ण हो जाता है।

तीसरी मान्यता

भारतीय ज्योतिषियों ने समय की धारणा को सिद्ध धरती के सूर्य की परिक्रमा के आधार पर नहीं प्रतिपादित किया है। उन्होंने संपूर्ण तारामंडल में धरती के परिभ्रमण के पूर्ण कर लेने तक की गणना करके वर्ष के आगे के समय को भी प्रतिपादित किया है। वर्ष को 'संवत्सर' कहा गया है। 5 वर्ष का 1 युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इद्वत्सर, अनुवत्सर और युगवत्सर ये युगात्मक 5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। 12 युगों के नाम हैं- प्रजापति, धाता, वृष, व्यय, खर, दुर्मुख, प्लव, पराभव, रोधकृत, अनल, दुर्मति और क्षय। प्रत्येक युग के जो 5 वत्सर हैं, उनमें से प्रथम का नाम संवत्सर है। दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां युगवत्सर है।

चौथी मान्यता

ऋग्वेद के अन्य 2 मंत्रों से 'युग' शब्द का अर्थ काल और अहोरात्र भी सिद्ध होता है। 5वें मंडल के 76वें सूक्त के तीसरे मंत्र में 'नहुषा युगा मन्हारजांसि दीयथः' पद में युग शब्द का अर्थ 'युगोपलक्षितान कालान प्रसरादिसवनान अहोरात्रादिकालान वा' किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उदय काल में युग शब्द का अन्य अर्थ अहोरात्र विशिष्ट काल भी लिया जाता था। ऋग्वेद के छठे मंडल के नौवें सूक्त के चौथे मंत्र में 'युगे-युगे विदध्यं' पद में युगे-युगे शब्द का अर्थ 'काले-काले' किया गया है। वाजसनेयी संहिता के 12वें अध्याय की 11वीं कंडिका में 'दैव्यं मानुषा युगा' ऐसा पद आया है। इससे सिद्ध होता है कि उस काल में देव युग और मनुष्य युग ये 2 युग प्रचलित थे। तैतिरीय संहिता के 'या जाता ओ वधयो देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा' मंत्र से देव युग की सिद्धि होती है।

पांचवीं मान्यता

धरती अपनी धूरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात 60 घटी में 1,610 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से घूमकर अपना चक्कर पूर्ण करती है। यही धरती अपने अक्ष पर रहकर सौर मास के अनुसार 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जबकि चन्द्रमास के अनुसार 354 दिनों में सूर्य का 1 चक्कर लगा लेती है। अब सौरमंडल में तो राशियां और नक्षत्र भी होते हैं। जिस तरह धरती सूर्य का चक्कर लगाती है उसी तरह वह राशि मंडल का चक्कर भी लगाती है। धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने या चक्कर लगाने में कुल 25,920 साल का समय लगता है। इस तरह धरती का एक भोगकाल या युग पूर्ण होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 26,000 वर्ष बाद हमेशा ही उत्तर में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा अपनी दिशा बदलकर पुनः उत्तर में दिखाई देने लगता है।

सूर्योपासना के समय जपें ये खास मंत्र

महिलाओं को रविवार और सोमवार को सूर्योपासना से घर में समृद्धि व गर्भवती महिलाओं को गुणी पुत्र की प्राप्ति होती है। बह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इन दिनों में खेजड़ी के पेड़ के नीचे प्रातः काल सूर्योपासना करते हुए इस मंत्र का 51 बार जाप करने से लाभ मिलता है-

नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः।
नमः पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तु ते।।
ओम आदित्याय नमः।

आत्मबल, बुद्धि, इन्द्रियों में सौम्यता, शिष्टता, काम, क्रोधादि शमन व मानसिक पीड़ा से मुक्ति के लिए इन महीनों में आने वाले हर रविवार को खेजड़ी के नीचे सूर्य के सामने बैठ इस मंत्र का 51 बार वाचन करें। पेड़ के नीचे की मिट्टी को लाकर घर में फेंकना शुभ होता है।

ओम नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः।
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः।।
ओम सूर्याय नमः।

जिन महिलाओं को संतान सुख न हो, ऐसी महिलाओं को आंवले के पेड़ के नीचे अथर्ववेद के इस मंत्र का 101 बार जाप व सूर्य देव को जल सिंचन करने से संतान प्राप्ति सुख संभव है-

परिहस्त विधारय योनिं गर्भाय धातवे।
ओम भास्कराय नमः।

नीलें रंग के अपराजिता (विष्णुकान्ता) नामक पौधे के नीचे इस मंत्र का जाप करने से घर के मुकदमेबाजी व न्यायालय में विजय, घर में समृद्धि व स्नायु तंत्र (नर्वस सिस्टम), चर्म रोग व श्वसन संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। इस पौधे के न होने की दशा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य को जल सिंचन कर इस मंत्र का 101 बार जाप करें -

ओम विश्वानिदेव सवितुः दुरितानि परांसुवः
यद् भद्रं तन्नासुवः। सूर्य कृणोतु भेशजं
चन्द्रमा वोपोच्छतु।।
ओम सूर्याय नमः।

दीर्घायु व हृदय संबंधी बीमारियों के लिए आश्विन व कार्तिक मास के प्रति रविवार बड़, ढाक, अशोक या सूर्यमुखी पौधे के नीचे आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें या अथर्ववेद के इस मंत्र का 51 बार जाप करें -

उत सूर्योदिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन।
ओम भानवे नमः।

कुशाग्र बुद्धि, इंटरव्यू में सफलता व शिक्षा से जुड़े पक्षों तथा वायु संबंधी रोगों के निवारण के लिए अथर्ववेद के इस मंत्र का पीपल के पेड़ के नीचे प्रातः काल हर रविवार इस मंत्र के जाप से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पुरुषः।
त्वं सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वं नोअसियज्ञिया।।
ओम सूर्याय नमः।

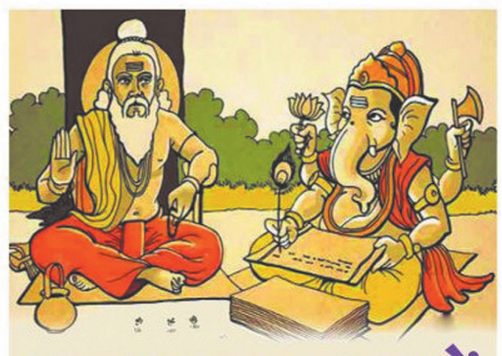

महाभारत काल में हुआ था गणेशजी का गजानन अवतार

मोदक प्रिय श्री गणेशजी विद्या-बुद्धि और समस्त सिद्धियों के दाता हैं तथा थोड़ी उपासना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें हिन्दू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उन्हीं का स्मरण और पूजन किया जाता है। गणेशजी ने तीनों युग में जन्म लिया है और वे आगे कलयुग में भी जन्म लेंगे।

धर्मशात्रों के अनुसार गणपति ने 64 अवतार लिए, लेकिन 12 अवतार प्रख्यात माने जाते हैं जिसकी पूजा की जाती है। अष्ट विनायक की भी प्रसिद्धि है। आओ जानते हैं उनके द्वापर के अवतार गजानन के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

- द्वापर युग में उनका वर्ण लाल है। वे चार भुजाओं वाले और मूषक वाहन वाले हैं तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं।
- द्वापर युग में गणपति ने पुनः पार्वती के गर्भ से जन्म लिया व गणेश कहलाए।
- परंतु गणेश के जन्म के बाद किसी कारणवश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर पराशर मुनि ने उनका पालन-पोषण किया। ऐसा भी कहा जाता है कि वे महिष्मति वरेण्य वरेण्य के पुत्र थे। कुरुप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था।
- इन्हीं गणेशजी ने ही ऋषि वेदव्यास के कहने पर महाभारत लिखी थी।
- इस अवतार में गणेश ने सिंदुरासुर का वध कर उसके द्वारा कैद किए अनेक राजाओं व वीरों को मुक्त कराया था।
- इसी अवतार में गणेश ने वरेण्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में शाश्वत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया।

सुनसान जगह पर नहीं रहना चाहिए घर

हिन्दू पुराणों और वास्तु शास्त्र में कुछ जगहों पर एक सभ्य व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। यदि वह वहां रहता है तो निश्चित ही उसके जीवन और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। घर यह सुकून का नहीं है तो कैसे जीवन में सुकून आएगा। जैसे चौराहे, तिराहे, अवैध गतिविधियों वाली जगह, शोर मचाने वाली दुकान या फैक्ट्री आदि। इन्हीं में से एक है सुनसान इलाका। दरअसल, आप जहां रहते हैं उस स्थान से ही आपका भविष्य तय होता है। यदि आप गलत जगह रह रहे हैं तो अच्छे भविष्य की आशा मत कीजिये। आओ जानते हैं कि क्यों नहीं रहना चाहिए सुनसान जगह पर।

- दो तरह के सुनसान होते हैं एक मरघट की शांति वाले और दूसरे एकांत की शांति वाले। कई लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसके चलते वे सुनसान में रहने चले जाते हैं। सुनसान जगह पर रहने के कई खतरें हैं और साथ ही शास्त्रों में ऐसी जगहों पर रहने की मनाही है।
- भविष्य पुराण अनुसार आपका घर नगर या शहर के बाहर नहीं होना चाहिए। गांव या शहर में रहना ही तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित होता है।
- यदि घर बहुत सुनसान स्थान पर या शरह-गांव के बाहर होगा तो जब भी आप घर से बाहर कहीं जाएंगे उस दौरान आपके मन और मस्तिष्क में घर-परिवार की चिंता बनी रहेगी।
- यह तो आप भी जाते होंगे कि सभी सुनसान स्थान पर अपराधी आसानी से अनिष्ट संबंधी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।
- दूसरी बात यदि शहर से दूर घर है तो रात-बिरात आने जाने में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भले ही आपके पास कार या बाइक हो।
- सुनसान जगहों को राहु और केतु की बुराई का स्थान माना जाता है। यहां पर घटना और दुर्घटना के योग बने रहते हैं।
- सुनसान जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचार बहुत तेजी से पनपते हैं।
- जहां अस्पताल, विद्यालय, नदी, तालाब, स्वजन या मनुष्य की आबादी नहीं है वहां पर नहीं रहना चाहिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी ने बंगाल के मतदाताओं के लिए भावुक संदेश लिखा

कोलकाता। साल 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा होने जा रहा है। यहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच है। 294 सीट पर कांटे की टक्कर है। भाजपा और टीएमसी के बड़े नेता लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी लगातार तीन बार (2011, 2016 और 2021) विजयी पताका फहरा चुकी है और चौका लगाने वाली है। वाम दल और कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्य की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने जय मां काली का नारा पेश किया और बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के कथित मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी दोहराया कि महिलाओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2021 में भाजपा ने 77 सीट पर कब्जा किया था। भाजपा के राजनीतिक संदेश में एक सोची-समझी रणनीति का संकेत है।

एनसीपी चीफ शरद पवार की तबीयत फिर बिगड़ी

मुंबई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार को रविवार को हल्के डिहाइड्रेशन के बाद पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इससे पहले उन्हें 9 फरवरी को सीने में इन्फेक्शन के बाद उसी रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था और 14 फरवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। एनसीपी चीफ की हालत स्थिर है और डिस्चार्ज होने से पहले वे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहेंगे। हॉस्पिटल के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट और चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. पुरवेज़ ग्रांट ने एक बयान में कहा, उन्हें हल्के डिहाइड्रेशन के लिए रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है और उन्हें इंट्रावीनस फ्लूइड की ज़रूरत है। उनकी हालत स्थिर है। वे दो दिनों तक हॉस्पिटल में रहेंगे और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किए जाने की उम्मीद है। डॉ. ग्रांट और हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. अभिजीत लोढ़ा उनके इलाज की देखरेख कर रहे थे।

कोटद्वार के मोहम्मद दीपक की दिल्ली में राहुल से मुलाकात

देहरादून। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी गर्मजोशी के साथ दीपक के गले लगे। कोटद्वार पटेल मार्ग पर एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर उभरे विवाद के बीच मोहम्मद दीपक चर्चा में आया था। मामले में तब और तूल पकड़ा जब राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्वीट किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचार विभाग के सचिव वैभव वालिया के नेतृत्व में कोटद्वार के दीपक ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से सोमवार को नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। वालिया ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोटद्वार के हमारे भाई दीपक कुमार को अपने आवास पर आमंत्रित कर उनसे आत्मीय मुलाकात की। दीपक कुमार जो अपने मानवीय कार्यों और इंसानियत की मिसाल के रूप में देशभर में पहचान बना चुके हैं, से राहुल गांधी ने स्नेहपूर्ण संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया।

ग्वालियर से यूथ कांग्रेस के पांचवां आरोपी गिरफ्तार

नईदिल्ली। भारत मंडपम में आयोजित हाई-प्रोफाइल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए व्यवधान के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस मामले के पांचवें आरोपी जितेन्द्र यादव को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। आरोपी यादव यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसे अदालत ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल पांच आरोपियों को शिकंजे में ले चुकी है। इससे पहले कांग्रेस यूथ विंग के चार अन्य कार्यकर्ताओं- कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव- को हिरासत में लिया गया था। शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने इन चारों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। शुक्रवार को नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने भारत मंडपम वेन्यू पर एक हाई-प्रोफाइल प्रोटेस्ट किया।

मुकुल रॉय का निधन 71 वर्ष की आयु में अंत

कोलकाता। भारतीय राजनीति के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय का सोमवार तड़के कोलकाता के साल्ट लेक स्थित अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, रात लगभग 1:30 बजे दिल का दौरा (कार्डियक अरेस्ट) पड़ने से उन्होंने अंतिम सांस ली। मुकुल रॉय पिछले 2-3 वर्षों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसके कारण वह सक्रिय राजनीति से दूर थे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी यूपीए सरकार के दौरान रॉय ने शिपिंग मिनिस्ट्री और बाद में रेल मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। रॉय के निधन पर, भारतीय जनता पार्टी नेता दिलीप घोष ने उन्हें एक अनुभवी नेता बताया और कहा कि वह पिछले दो-तीन सालों से बीमार थे और राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। घोष ने हड्डू से बात करते हुए कहा, वह एक अनुभवी पॉलिटिशियन थे। वह यूनियन मिनिस्टर भी बने।

एआई की दुनिया में भारत का डंका!

भारतीय युवाओं का सामर्थ्य पूरी मानवता के काम आएगा

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की युवा प्रतिभाओं के सामर्थ्य को अब पूरी दुनिया ने पहचान लिया है। पिछले सप्ताह दिल्ली में संपन्न हुए इस शिखर सम्मेलन ने न केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत की, बल्कि एआई (एआई) के भविष्य को लेकर एक नई वैश्विक दिशा भी तय की है।

पिछले सप्ताह नयी दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन का समापन 'एआई इम्पैक्ट' पर नयी दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने के साथ हुआ, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर वैश्विक सहयोग में मील का पत्थर है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''दिल्ली में हुए ऐतिहासिक एआई शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य की जमकर सराहना की है। इससे पता चलता है कि प्रौद्योगिकी को लेकर हमारे युवा साथियों की सोच पूरी मानवता के बहुत काम आने वाली है।''

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के घोषणापत्र पर 89 देशों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं जो आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई का लाभ उठाने पर व्यापक वैश्विक सहमति को दर्शाता है। इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पॉहमेलॉ सहित दुनिया भर के नेता और कई प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उपस्थित थे।

कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेई प्लेनकोविक, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लै, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो भी शामिल हुए।

सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की विषय वस्तु पर आधारित इस शिखर सम्मेलन को भारत को एआई के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में एक ऐसे भविष्य की कल्पना की गई जिसमें एआई मानवता को आगे बढ़ाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और पृथ्वी के हितों की रक्षा करने में मदद करे।

कौन होगा इंडिया ब्लॉक का लीडर?

मणि शंकर अय्यर ने राहुल के नेतृत्व पर उठाए गंभीर सवाल

नईदिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उनसे इंडिया ब्लॉक के नेता पद से इस्तीफा देने का आग्रह किया है। अय्यर ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एम.के. स्टालिन और तेजस्वी यादव सहित कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के नाम गांधी के बाद यह भूमिका संभालने के संभावित उम्मीदवारों के रूप में सुझाए। कांग्रेस पार्टी की हालिया चुनावी हार का जिक्र करते हुए उन्होंने जोर दिया कि ये नेता गठबंधन को मजबूत करने और सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक समय दे सकते हैं।

अय्यर ने कहा कि हम इतने अक्षम थे कि हमने ममता बनर्जी को दूर रखा, और इसी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी इस पद को अपने पास रखने की कोशिश करने के बजाय क्षेत्रीय पार्टी नेताओं—चाहे वह स्टालिन हों, ममता दीदी हों, अखिलेश हों, तेजस्वी हों या कोई और—को कमान संभालने देंगे। शायद वे ज्यादा समय दे पाएंगे। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि केवल राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक का प्रभावी नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल राहुल गांधी ही भाजपा को टक्कर दे सकते हैं।

यह पहली बार नहीं है जब मणि शंकर अय्यर ने कांग्रेस के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पिनारयी विजयन केरल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब कांग्रेस राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। अय्यर ने यह टिप्पणी %विजन 2031= विकास और लोकतंत्र% शीर्षक वाले अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलते हुए की, जिसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने किया। उन्होंने विजयन की प्रशंसा की और सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में केरल की स्थिति को मजबूत करने के लिए संशोधन किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, जो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, मैं एक बार फिर अपनी अपील दोहराता हूं कि केरल को देश का सर्वश्रेष्ठ पंचायती राज राज्य बनाने के लिए, व्यावहारिक अनुभव, थॉमस आइज़ैक के विचारों, मेरी अध्यक्षता में तैयार की गई पांच खंडों वाली रिपोर्ट और वी.के. रामचंद्रन द्वारा जिला नियोजन पर योजना आयोग द्वारा प्रसारित नोट के आधार पर राज्य कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए, जब आयोग ने वास्तव में पंचायती राज का समर्थन किया था।

तमिलनाडु चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर रार तेज

एमएमके ने डीएमके से मांगी पांच सीटें

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सीट बंटवारे को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कषगम और उसके सहयोगी दलों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मनिथनेया मक्कल कच्ची के अध्यक्ष एम.एच. जवाहिरुल्लाह ने डीएमके मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में पार्टी नेताओं से मुलाकात की। बैठक में एमएमके ने आगामी चुनाव में कम से कम पांच सीटें देने की मांग रखी है।

जवाहिरुल्लाह ने मीडिया से कहा कि यह बातचीत का पहला दौर है और आगे भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में एमएमके ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों सीटें जीती थीं। पार्टी का दावा है कि उसका तमिलनाडु के सभी जिलों में संगठन मजबूत है और युवाओं व महिलाओं की बड़ी टीम उसके साथ काम कर रही है। एमएमके ने साफ किया कि वह डीएमके गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के पक्ष में पूरे राज्य में प्रचार करेगी।

एमएमके ने यह भी मांग की है कि न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके के मुस्लिम नेताओं को भी पर्याप्त टिकट दिए जाएं। जवाहिरुल्लाह ने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली डीएमके को मुस्लिम गठबंधन दलों को कुल मिलाकर 16 सीटें देनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा।

इससे पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष केएम कादर मोहिद्दीन ने भी डीएमके नेताओं से मुलाकात कर पांच सीटों की मांग की थी। डीएमके की सीट बंटवारा समिति में टीआर बालू, केएन नेहरू, ईवी वेलु, तिरुचि शिवा, आरएस भारती और एमआरके पन्नीरसेल्वम शामिल रहे। समिति ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी परामर्श किया। वहीं नाम तमिलर कच्ची ने 234 उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख सीमन ने कराईकुडी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सूची में 117 पुरुष और 117 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। दूसरी ओर एआईएडीएमके ने भी चुनावी वादों का ऐलान कर दिया है। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा के लिए इस साल चुनाव होना है। 2021 में डीएमके ने 133 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि एआईएडीएमके को 66 सीटें मिली थीं।

डीएमके-कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर अहम बैठक

तमिलनाडु की सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर रविवार को बातचीत शुरू कर दी। इसी बीच कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से उनके अलवरपेट स्थित आवास पर मुलाकात की। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के सूत्रों के अनुसार, लगभग 45 मिनट की बैठक में वेणुगोपाल ने स्टालिन को अपनी पार्टी की अपेक्षाओं और उन निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बताया, जहां वह चुनाव लड़ना चाहती है।

खेल
प्रमुख समाचार

टीम इंडिया को खल रही विराट कोहली की कमी!

नईदिल्ली। टीम इंडिया को अक्सर भावनाओं के आईने में देखा जाता है। शायद यही वजह है कि हालिया नतीजों ने सिर्फ आंकड़ों की चिंता नहीं बढ़ाई, बल्कि एक खालीपन का अहसास भी कराया। टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार को अगर केवल एक मैच की तरह देखा जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी।

यह हार दरअसल उस दौर का प्रतिबिंब है, जिसमें टीम अपने नए स्वरूप की तलाश कर रही है। इसी तलाश में एक नाम बार-बार याद आता है, वह है विराट कोहली। कोहली की मौजूदगी का मतलब हमेशा सिर्फ शतक या बड़े स्कोर नहीं रहा। उनकी बल्लेबाजी में एक लय होती थी, जैसे पारी किसी अदृश्य धागे से बंधी हो। जब वे क्रीज पर होते थे तो मैच की गति अचानक स्थिर लगने लगती थी, मानो उतावलापन खुद ही धीमा पड़ गया हो। मौजूदा टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन वही भरोसा कि कोई है, जो पारी को संभाल लेगा। अक्सर टूटता हुआ सा लगता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भी यही अहसास बार-बार उभरा। भारत ने ऐसे क्षण देखे, जब मैच हाथ में लग रहा था, लेकिन क्रिकेट का खेल अक्सर उन्हीं पलों में पलटता है, जब संयम और स्पष्टता की जरूरत होती है। साझेदारियां बनते-बनते टूट गईं। रन गति का उतार-चढ़ाव यह बताता रहा कि टीम अभी अपनी धड़कन की सही रफ्तार खोज रही है। यह किसी कमजोरी से ज्यादा उस स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे हर नई पीढ़ी गुजरती है। स्पिन की चुनौती ने इस कहानी को और गंभीर बना दिया है। बल्लेबाजों का संघर्ष सिर्फ तकनीक का नहीं, धैर्य का भी दिखता है। कुछ पलों में वे बहुत सतर्क दिखते हैं तो कुछ में जरूरत से ज्यादा जल्दबाज। यही उतार-चढ़ाव क्रिकेट को खेल से ज्यादा एक मानसिक यात्रा बना देता है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 480 अंक चढ़ा निफ्टी 25713 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से पॉजिटिव संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार (23 फरवरी) को मजबूती के साथ बंद हुए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कुछ टैरिफ नियमों को खारिज कर दिया है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 100 से ज्यादा अंक चढ़कर 82,906 पर खुला। खुलते ही इसमें तेजी देखने को मिली और 83 हजार के पार चला गया। कारोबार के दौरान यह 650 अंक तक चढ़ गया था। अंत में 479.95 अंक या 0.58 फीसदी की बढ़त लेकर 83,294.66 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी मजबूती के साथ 25,678 अंक पर खुला और खुलने के कुछ ही देर में 25,700 के ऊपर चला गया। अंत में 141.75 अंक या 0.55 फीसदी की बढ़त के साथ 25,713 पर बंद हुआ।

त्योहार भी नहीं बचा पाए रिटेल सेक्टर को! बिक्री गिरी

नईदिल्ली। त्योहारों के बावजूद कपड़ा रिटेल सेक्टर में इस बार उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं हुई। तीसरी तिमाही में कई कंपनियों को बिक्री के मोर्चे पर दबाव झेलना पड़ा। हालांकि कुछ कंपनियों ने खर्च कम करके अपने मुनाफे को संभाल लिया। Nuvama Institutional Equities की रिपोर्ट के अनुसार इस बार दुर्गा पूजा की खरीदारी दूसरी तिमाही में ही ज्यादा हो गई थी। इसी वजह से तीसरी तिमाही में खासकर नॉर्थ ईस्ट इलाके में बिक्री कम रही। इसका असर सस्ती श्रेणी के रिटेल स्टोर्स पर ज्यादा दिखा। Style Bazaar, V2 और VMart जैसी कंपनियों की समान स्टोर बिक्री कमजोर रही। Trent की समान स्टोर बिक्री में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है, इसलिए बाजार ने इसे गंभीरता से लिया।

हाउसिंग कमजोर, फिर भी सीमेंट की डिमांड मजबूत

नईदिल्ली। सीमेंट सेक्टर में सुस्ती का दौर खत्म होता दिख रहा है। Nuvama Institutional Equities की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में सीमेंट की मांग और कीमतों दोनों में सुधार दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि यह सुधार ऐसे समय में आया है जब जनवरी में केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का पूंजीगत खर्च सालाना आधार पर तेज गिरावट में था। रिपोर्ट बताती है कि वित्तवर्ष 25 में सुस्त पड़ी कैपेक्स की रफ्तार वित्तवर्ष 26 में फिर पटरी पर लौट आई है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत खर्च में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार ने वित्तवर्ष 26 के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये का कैपेक्स बजट रखा है, जिसमें से दिसंबर तक लगभग 70 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है। इतना ही नहीं, वित्तवर्ष 27 के लिए यह आवंटन बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

590 करोड़ रू. धोखाधड़ी से हिला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

नईदिल्ली। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरो सोमवार (23 फरवरी) को बाजार में खुलते ही औंधे मुंह लुढ़क गए और बीएसई पर 20 प्रतिशत के निचले सर्किट पर पहुंच गए। बैंक के शेयरों में ये गिरावट चंडीगढ़ की एक ब्रांच में लगभग 590 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के चलते आई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ खुले। लेकिन बिकवाली का दबाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिखे और गिरावट जारी रही। बैंक ने जांच पूरी होने तक चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। चंडीगढ़ की एक ही ब्रांच में 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आने के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरधारकों को बड़ा नुकसान हुआ। सोमवार को एक ही दिन में बैंक का मार्केट कैप करीब 14,438 करोड़ रुपये घट गया।

डिजिटल युग की कला: अभिव्यक्ति से अनुभव तक की सांस्कृतिक यात्रा

शैलेश शुक्ला

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में मानव सभ्यता जिस तीव्र परिवर्तनशील दौर से गुजर रही है, उसमें यदि किसी एक क्षेत्र ने सबसे व्यापक, बहुआयामी और गहन रूपांतरण अनुभव किया है, तो वह है—कला का संसार। कला, जो कभी कैनवास, मंच और सभागार तक सीमित मानी जाती थी, आज डिजिटल मीडिया की शक्ति से वैश्विक, त्वरित और सहभागी अनुभव में रूपांतरित हो चुकी है।

यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और दार्शनिक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, इमर्सिव तकनीक और एल्गोरिद्मिक दृश्यता ने कला की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देते हुए उसे एक नए युग में प्रवेश करा दिया है, जहाँ कलाकार, दर्शक और तकनीक—तीनों सह-निर्माता बन गए हैं।

कला का इतिहास सदैव तकनीकी नवाचारों से प्रभावित रहा है। मुद्रण तकनीक ने साहित्य को जनसामान्य तक पहुँचाया, कैमरे ने दृश्य यथार्थ को नया आयाम दिया और सिनेमा ने कथा-कला को वैश्विक भाषा बना दिया। इसी क्रम में डिजिटल मीडिया ने कला को नेटवर्क आधारित अनुभव में बदल दिया है।

अब कला स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि गतिशील प्रक्रिया है जो ऑनलाइन मंचों पर जन्म लेती है, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती है और वैश्विक दर्शकों की सहभागिता से विकसित होती है। मोबाइल स्क्रीन, लाइव स्ट्रीमिंग और इंटरैक्टिव ऐप्स ने कला के उपभोग के पारंपरिक ढाँचे को तोड़ दिया है। परिणामस्वरूप कला अब स्थान-निर्भर नहीं

रही; वह सर्वत्र उपलब्ध अनुभव बन गई है।

दृश्य कला के क्षेत्र में यह परिवर्तन विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। डिजिटल पेंटिंग, 3ष्ठ मॉडलिंग, वीडियो आर्ट, एनीमेशन और डेटा-आधारित कला ने सृजन की प्रक्रिया को पूरी तरह पुनर्परिभाषित कर दिया है। कलाकार अब केवल ब्रश या रंगों तक सीमित नहीं, बल्कि कोड, एल्गोरिद्म और डिजिटल टूल्स के माध्यम से भी कला रच रहे हैं। छवि, ध्वनि और डेटा के संयोजन से निर्मित इमर्सिव अनुभव दर्शक को कला के भीतर प्रवेश करने का अवसर देते हैं। इस प्रकार कला देखने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने का अनुभव बनती जा रही है। यह प्रवृत्ति इस बात का संकेत है कि भविष्य की कला बहु-संवेदी होगी, जिसमें दृश्य, श्रव्य और स्पर्शात्मक तत्व एक साथ सक्रिय होंगे।

प्रदर्शनकारी कला में भी डिजिटल परिवर्तन उतना ही गहरा है। नृत्य, संगीत, रंगमंच और लोक मंचन जैसे पारंपरिक रूप अब वर्चुअल मंचों पर नए अवतार में प्रकट हो रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्सर्ट, ऑनलाइन थिएटर, डिजिटल नृत्य प्रस्तुति और मेटावर्स शो दर्शाते हैं कि मंच अब भौतिक सीमा में कैद नहीं रहा। महामारी के बाद यह परिवर्तन और तीव्र हुआ, जब कलाकारों ने डिजिटल माध्यमों को न केवल विकल्प, बल्कि स्थायी मंच के रूप में स्वीकार किया। आज दर्शक किसी भी देश में बैठकर विश्व के किसी भी कलाकार की प्रस्तुति का हिस्सा बन सकता है। इस वैश्विक पहुंच ने कला को अभूतपूर्व लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया है।

डिजिटल मीडिया ने कला को केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ही नहीं, बल्कि आर्थिक उद्योग में भी बदल दिया है। गेमिंग, एनीमेशन, डिजिटल विज्ञापन, कंटेंट क्रिएशन और वर्चुअल प्रदर्शन जैसे क्षेत्रों ने लाखों नए रोजगार अवसर उत्पन्न किए हैं। डिजिटल विज्ञापन उद्योग की तेज़ वृद्धि ने दृश्य कला, मोशन ग्राफिक्स और प्रदर्शनकारी प्रस्तुति की माँग को बढ़ा दिया है। अब ब्रांड संचार में कथा-आधारित वीडियो, डिजिटल परफॉर्मेंस और इमर्सिव अनुभव प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इससे कलाकारों के लिए नए पेशे उभरे हैं—जैसे डिजिटल स्टोरीटेलर, मोशन डिजाइनर, वर्चुअल अभिनेता और इंटरैक्टिव कलाकार। यह संकेत है कि कला अब केवल सौंदर्यबोध का क्षेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बन चुकी है।

राज्यपाल डेका ने प्रदेश की 6वीं विधानसभा के अष्टम् सत्र को किया संबोधित

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज छत्तीसगढ़ की 6 वीं विधानसभा के अष्टम् सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल डेका का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने स्वागत किया। अभिभाषण का मूल पाठ इस प्रकार है, आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना और हमारी विधानसभा की रजत जयंती की बहुत-बहुत बधाई। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से हमारी विधानसभा के नवीन भवन का लोकार्पण हुआ। आप सभी को लोकतंत्र के मंदिर इस नये भवन की हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रदेश की षष्ठम् विधानसभा के वर्ष 2026 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 4. अब हमारे प्रदेश ने विकसित राज्य की ओर अपना नया सफर शुरू किया है। सामूहिक प्रयत्न और संकल्प से निश्चित रूप से हम वर्ष 2047 तक विकसित राज्य का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। 5. भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राज्य का निर्माण किया। उन्होंने जिस संकल्पना को लेकर छत्तीसगढ़ बनाया, उसे पूरा होते देखकर बहुत खुशी होती है।

छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहां की सरल, सहज और मेहनतकश जनता की बदौलत मेरी सरकार इन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है। मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंत्योदय का कल्याण है। मेरी सरकार की प्रत्येक नीति में यह सोच है कि इसके लागू होने से आखिरी पंक्ति में खड़े नागरिक को किस तरह से लाभ मिलेगा। जब इस सोच के अनुरूप नीति बनती है तो समावेशी विकास की दिशा में कदम स्वत: बढ़ जाते हैं।

समावेशी विकास में महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। मातृ शक्ति को सशक्त बनाना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ इस वर्ष को 'महतारी गौरव वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। 9. सामाजिक कल्याण के साथ तीव्र

आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नये जमाने के अनुरूप मेरी सरकार ने नवाचार भी किया है जिसका व्यापक असर प्रदेश के आर्थिक विकास के आंकड़ों में नजर आता है। विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब किसान मजबूत और समृद्ध होंगे। इसलिए मेरी सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने, फसल का उचित मूल्य दिलाने और बाजार तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

इस वर्ष 25 लाख 24 हजार किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और 33 हजार 431 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। मेरी सरकार ने 'कृषक उन्नति योजना' के तहत होली से पहले किसानों को 10 हजार 292 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी किसान हितैषी सरकार है। छत्तीसगढ़ के 24 लाख 72 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। मेरी सरकार के कल्याणकारी दायरे में भूमिहीन कृषक मजदूर भी शामिल हैं। राज्य के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को 'दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना' के तहत सालाना 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। मेरी सरकार गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों को उपलब्ध कराने की दिशा में पुख्ता काम कर रही है। बीज उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के किसानों को प्रमाणीकरण शुल्क में शतप्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। दो साल में 21 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये हैं। हमारे किसान भाइयों द्वारा उपजाया खाद्यान्न निर्यात के माध्यम से विदेशों तक अधिकाधिक पहुंचाया जाए, इसके लिए मेरी सरकार ऐसी तकनीकों पर काम कर रही है जिससे खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता से 06 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। दुनिया भर में खेती-किसानी की तकनीक बदल रही है। कृषि शोध में लगे अध्यापकों और छात्रों को मेरी सरकार द्वारा निरंतर एक्सपोजर विजिट भी कराया जा रहा है। प्रदेश में दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। 'दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना' में प्रति क्विंटल दिए जाने वाले 1000 रूपए के अनुदान को अब बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है। 'अक्ती बीज संवर्धन योजना' के तहत तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर अनुदान राशि 1000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने धान के बदले अन्य खरीफ फसल लेने वाले कृषकों को भी प्रति एकड़ 11 हजार रुपए आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। खाद्यान्न तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पाम ऑयल को बढ़ावा दे रही है। मेरी सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान के अतिरिक्त 69 हजार 620 रुपए का टापअप अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में कोदो और रागी जैसे मिलेट्स की खेती में बड़ी संभावना है और इसके बीजों के आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मेरी सरकार प्रयासरत है। हमारे वनांचल जैविक खेती के लिए सबसे अनुकूल हैं और इससे स्थानीय किसानों के लिए बड़े लाभ की संभावनाएं खुलेंगी। प्रदेश में 38 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है। हमारा छुईखदान पान की बेलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मेरी सरकार ने यहां पान अनुसंधान केंद्र आरंभ किया है। खेती-किसानी से जुड़ी अर्थव्यवस्था का विस्तार पशुपालन को बढ़ावा दिए बिना संभव नहीं है। मेरी सरकार ने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू किया है। सहकारिता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत से लोगों को जोड़ते हुए 'सहकार से समृद्धि योजना' के तहत 488 नवीन डेयरी समितियों का गठन किया गया है। दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से महासंघ द्वारा दूध का क्रय मूल्य 35 रुपए से बढ़ाकर 36 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है।

संत गाडगे बाबा ने दिया स्वच्छता ही सच्ची पूजा का संदेश: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्र संत शिरोमणि गाडगे बाबा की 150वीं जयंती पर आयोजित निर्मल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी ऐसे महान संत का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन और कर्मों से समाज को स्वच्छता, सेवा और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संत गाडगे बाबा ने स्वच्छता ही सच्ची पूजा का जो संदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत गाडगे बाबा की स्वच्छता की प्रेरणा से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान का स्मरण हो गया। उन्होंने कहा कि 15

अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और आज स्वच्छता जनआंदोलन बन चुकी है।

उन्होंने कहा कि यह संत गाडगे बाबा के विचारों का ही प्रभाव है कि देश में स्वच्छता के प्रति व्यापक जागरूकता आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी माताओं-बहनों को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। देशभर में शौचालयों के निर्माण से उनकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक योजनाएँ शुरू की गईं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलें शामिल हैं। आज सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों तक पहुँच रहा है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़े हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश आर्थिक रूप से निरंतर मजबूत हो रहा है और हम सभी विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के साथ-साथ विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण भी हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के हर वर्ग का सम्मान बढ़े और सभी समुदाय विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है।।

भाजपा ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए कई नाम भेजे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव ऐलान हो गया है और 26 मार्च से नामांकन होना है। इसी कड़ी में अब भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए दावेदारों के नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेज दिया है। पार्टी ने स्त्र-स्ट, ह्वस्ट और सामान्य वर्ग के नेताओं को पैनल में जगह दी है। कुल 7 नेताओं को इस पैनल में शामिल किया गया है। भाजपा की ओर हाईकमान को भेजे गए प्रस्ताव में नवीन मार्कंडेय, कृष्णमूर्ति बांधी और किरण बघेल, गौरीशंकर अग्रवाल, प्रबल प्रताप जूदेव और सरोज पांडे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल का नाम शामिल किया गया है। बता दें कि भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए जातिगत समीकरण को ध्यान रखा है। बता करें जाति के अनुसार उम्मीदवारों की तो स्ट वर्ग से नवीन मार्कंडेय, कृष्णमूर्ति बांधी और किरण बघेल को जगह दी गई है। वहीं, सामान्य वर्ग से गौरीशंकर अग्रवाल, प्रबल प्रताप जूदेव और सरोज पांडे को शामिल किया गया है। ओबीसी वर्ग से पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल का नाम हाईकमान को भेजा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में अब तक सिर्फ चर्चाएं ही चल रही है।

पीएम जनमन योजना में देश में नंबर 1 छत्तीसगढ़

रायपुर। प्रधानमंत्री जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 7 विशेष पिछड़ी जनजातियों के शत-प्रतिशत घर अब विकास की रोशनी से जगमगा रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर सुविधा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और छत्तीसगढ़ हर परिवार आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में राज्य प्रशासनिक सेवा तथा एलाइड सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह जनसेवा के व्यापक अवसरों और जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में झूठ परोसा गया: बैज

रायपुर। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सरकार ने चतुराई से अपनी नाकामी और असल आंकड़ों को छुपाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि ज़मीन हकीकत सरकार के कागजी दावों से बिल्कुल अलग है, पिछले बजट में छात्रवृत्ति के लिए आबंटित राशि का एक नया पैसा भी छात्रों को नहीं मिला। मुख्यमंत्री के गृह जिले कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी,

अब तक एक पत्थर भी नहीं रखा गया। स्कूलों में 60 हजार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन यह सरकार हर बार केवल घोषणा करती है, नई भर्तियां जानबूझकर रोक रखी है। 10463 स्कूल बंद कर दिये, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल सरकार की उपेक्षा से बदहाल है, सुपबेड़ा में एक बार फिर लोग आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी पीने मजबूर हैं। अस्पतालों में जांच, इलाज और दवा के अभाव में मरीज बेमौत मरने मजबूर हैं। आयुष्मान योजना से इलाज का भुगतान नहीं होने से निजी अस्पतालों में मरीजों को लाभ नहीं मिल रहा है। किसी भी सरकार के लिए बजट प्रावधान विजन डॉक्यूमेंट होता है, आने वाले वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और कार्ययोजना का ब्लूप्रिंट होता है।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक सम्पन्न हुई। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के साथ वादा खिलाफी, प्रदेश में प्रशासनिक आतंकवाद, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति, एस.आई.आर. के तहत मतदाता सूची से नामों की कटौती, धान खरीदी केन्द्रों में बोरा भराई एवं तौलाई के नाम पर किसानों से अवैध वसूली, प्रदेश में सड़कों के निर्माण प्रकिया में भ्रष्टाचार, प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट उत्सर्जन करने वाले उद्योगों द्वारा एन.जी.टी. की गाइडलाइन का उल्लंघन, बिजली बिल की दरों में वृद्धि, सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून का उल्लंघन।अध्यक्षता, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक गण कवासी लखमा, उपनेता लखेश्वर बघेल, सचेतक दलेश्वर साहू, उपसचेतक दिलीप लहरिया, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, भोलाराम साहू लालजीत सिंह राठिया, देवेन्द्र यादव, इंद्रशाह मंडावी, सावित्री मंडावी, विक्रम मंडावी, यशोदा निलाम्बर वर्मा, कुंवर सिंह निषाद, संगीता सिन्हा, अंबिका मरकाम, द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, उत्तरी गणपत जांगड़े, शेषराज हरबंश, अटल श्रीवास्तव, बालेश्वर साहू, ब्यास कश्यप, राघवेन्द्र सिंह, चतुरी नंद, फूलसिंह राठिया, कविता प्राणलहरे, संदीप साहू, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, इंद्र साव उपस्थित थे।

छग पुलिस के माधुरी बनी स्ट्रांग वूमेन छग

रायपुर। चंदू लाल साहू की स्मृति में 7 वी छग पावर लिफ्टिंग एवं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन लाखे नगर पुरानी बस्ती में किया गया। छग पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव मानिक ताम्रकार ने बताया कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में छग पुलिस की माधुरी सोनवानी स्ट्रांग वूमेन एवं पावर लिफ्टिंग में अंजना सिंह मनेंद्र गढ़ की 74 साल की कमला देवी मांगतानी मास्टर वर्ग में स्ट्रांग वूमेन बनी। जबकि पुरुष वर्ग में दल्ली राजहरा के सागर यादव स्ट्रांग मेन पर कब्जा जमाया। सब जूनियर वर्ग में आशीष यादव रायपुर को स्ट्रांग मेन का खिताब दिया गया।पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि ब्राह्मण पारा वार्ड के अजय साहू एवं प्रोटीन विला के डायरेक्टर दुर्गेश साहू ने सभी विजयी खिलाड़ी प्रथम 4000, द्वितीय 3000, तृतीय 2500 नगद राशि एवं मेडल से सम्मानित किया गया। सभी स्ट्रांग मेन वूमेन को प्रोटीन विला के तरफ से आकर्षक कप के साथ 1500 नगद ईनाम भी दिया गया। कुल टोटल 2 लाख रुपए कैश बांटे जो अब तक छग में पहली बार इतनी राशि पावर लिफ्टर को मिला। प्रतियोगिता में सभी प्रथम विजयी खिलाड़ी 1 से 4 अप्रैल को आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आगरा में भाग लेंगे।

स्वास्थ्य केंद्र मठपुरैना का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मठपुरैना का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, मेडिसिन विभाग, पंजीयन शाखा, ऑपरेशन थिएटर तथा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मठपुरैना का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली और निर्देशित किया कि किसी भी मरीज को दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं से बातचीत कर स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की।कलेक्टर ने अस्पताल के स्टाफ से दवा स्टॉक प्रबंधन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा स्वास्थ्य केंद्र में साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

डीएमएफ फंड प्रकरण में आरोपी अनिल टुटेजा गिरफ्तार

रायपुर। ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 02/2024 में विस्तृत विवेचना उपरांत आरोपी अनिल टुटेजा को विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्यों, दस्तावेजों तथा विभिन्न व्यक्तियों के कथन/बयानों से प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी द्वारा छ्तरूस्र निधि से संबंधित विभिन्न कार्यों में अपने परिचित व्यक्तियों एवं फर्मों को कमीशन/प्रतिफल लेकर कार्य दिलवाने तथा

कार्य आवंटन कराने में सक्रिय भूमिका निभाई गई। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने अपने रिश्तेदारों एवं निकट संबंधियों के माध्यम से विभिन्न फर्मों को कमीशन लेकर छ्तरूस्र मद के कार्य दिलवाने/ आवंटित कराने की गतिविधियाँ संचालित कीं। आरोपी द्वारा डीएमएफ फंड से संबंधित जिलों में कमीशन लेकर कार्य दिलवाने/ आवंटन कराने की गतिविधियाँ भी संचालित की जाती रही हैं। उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध शासकीय धन के दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र तथा भ्रष्ट आचरण से संबंधित संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया स्थापित पाए गए हैं। आरोपी को विधि अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 26.02.2026 तक पुलिस रिमांड की अनुमति प्राप्त की गई है।

होली पर लगभग 1600 से 1800 करोड़ के व्यापार की संभावना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेंद्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरिंदर सिंह, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंधान, वासु मखीजा, भरत जैन, राकेश ओचवानी तथा शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुमान के अनुसार आगामी होली के अवसर पर इस वर्ष प्रदेश सहित देशभर में लगभग 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होने की संभावना है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के व्यापार की तुलना में करीब 25 प्रतिशत अधिक है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का व्यापक प्रभाव बाजारों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस बार होली के अवसर पर भारतीय निर्मित हर्बल गुलाल, प्राकृतिक रंग, पिचकारियां, गुब्बारे, चंदन, पूजन सामग्री, परिधान तथा अन्य स्वदेशी उत्पादों की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है, जबकि वर्ष 2021 से पहले बाजारों में चीनी सामान का वर्चस्व हुआ करता था।

उन्होंने बताया कि होली से संबंधित वस्तुओं के अलावा मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स, गिफ्ट आइटम, फूल-फल, कपड़े, फर्निशिंग फैब्रिक, किराना, एफएमसीजी उत्पादों तथा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की भी बाजारों में भारी मांग देखी जा रही है। होली खेलने के लिए सफेद टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा, सलवार-सूट तथा हैप्पी होली लिखी टी-शर्ट भी बड़ी संख्या में खरीदी जा रही हैं। पारवानी ने बताया कि कैट के अनुमान के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ में लगभग 1600 से 1800 करोड़ रुपये के व्यापार की संभावना है। शहर के थोक और खुदरा बाजार रंग-बिरंगे गुलाल, आकर्षक पिचकारियों, गुजिया की मालाओं और ड्राई फ्रूट पैकों से सजे हुए हैं तथा दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मिठाई की दुकानों पर भी विशेष रूप से होली की पारंपरिक मिठाई गुजिया की बिक्री में बड़ा उछाल आया है।

उन्होंने बताया कि देशभर में होली मिलन समारोह बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में ही विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों द्वारा 3000 से अधिक होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके चलते बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस, होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक पार्क लगभग पूरी तरह बुक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में होलिका दहन 3 मार्च को होगा और रंगों की होली 4 मार्च को खेली जाएगी।

छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा: 12वीं के कई विषयों के पेपर शांतिपूर्ण, 1,985 छात्र अनुपस्थित

रायपुर। छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षाओं के तहत सोमवार को कक्षा 12वीं के विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्र शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। परीक्षा का संचालन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया गया। आज जिन विषयों की परीक्षा आयोजित हुई, उनमें राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, लेखा शास्त्र, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, वस्तु चित्रण एवं आलेखन, शारीरिक क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा शामिल रहे। मंडल से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन विषयों के लिए कुल 2,42,225 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 2,40,240 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए, जबकि 1,985

छात्र अनुपस्थित दर्ज किए गए। उल्लेखनीय बात यह रही कि पूरे राज्य में आज एक भी नकल प्रकरण सामने नहीं आया, जिसे परीक्षा प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

उड़नदस्ता टीम में मंडल की सचिव पुष्पा साहू और सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रदीप कुमार साहू शामिल रहे। टीम ने भिलाई क्षेत्र के नेहरू माध्यमिक विद्यालय खुर्सीपार, शासकीय कन्या शाला भिलाई-03, स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल चरोदा तथा जंजगिरी स्थित परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी केंद्रों पर परीक्षा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। कहीं भी अनुचित साधनों के उपयोग या परीक्षा नियमों के उल्लंघन की कोई शिकायत या मामला सामने नहीं आया। अधिकारियों ने केंद्राध्यक्षों और परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि आगामी परीक्षाएं भी इसी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.